राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस
क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रसारीत

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार, 16 जुलाई 2022 वर्ष-5, अंक-171 पृष्ठ-08 मूल्य-01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अखिलेश से नहीं टिकता किसी का गठबंधन, राजभर के झटके से पहले कांग्रेस, बीएसपी, शिवपाल ने भी दिए फटके

लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिनर में गए तो उनके अखिलेश यादव से अलग होने के चर्चे राजनीतिक गलियारों में होने लगे। अब दोनों ने घोषणा कर दी है कि वो 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में हैं। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जब वोट मांगने लखनऊ आए तो शिवपाल और राजभर दोनों की अनदेखी की गई। अखिलेश यादव ने रालोद नेता जयंत चौधरी को फोन किया लेकिन ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया। बाद में राजभर ने कहा कि ऐसा लगता है कि अखिलेश को अब उनकी जरूरत नहीं है। हालांकि राजभर अभी भी अखिलेश के साथ गठबंधन में हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने जाति आधारित छोटी पार्टियों से गठजोड़ कर मजबूत गठबंधन बनाया था। हाल के घटनाक्रम से पता चलता है कि गठबंधन टूटने की ओर बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और महान दल के तत्कालीन अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सपा से नाता तोड़ लिया और अब एसबीएसपी प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने भी सपा से अलग होने के संकेत दिए हैं। 2019 में सपा और बसपा ने गठबंधन किया। दोनों ने साथ चुनाव लड़ा और हार गए। इसी के बाद दोनों अलग हो गए। दोनों ही पार्टी अध्यक्षों ने एक दूसरे के काम पर सवाल उठाए। यहां तक कि सपा ने मायावती के कई नेता अपनी पार्टी से जोड़े।

प्रधानमंत्री मोदी ने के. कामराज को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि, ट्वीट कर कही ये बात

प्रधानमंत्री मोदी ने के. कामराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्कालीन मद्रास राज्य (अब तमिलनाडु) के पूर्व मुख्यमंत्री कामराज कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे के. कामराज को उनकी जयंती पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्होंने भारत की आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने के साथ ही एक करुणामयी प्रशासक के रूप में अपनी छाप छोड़ी। तत्कालीन मद्रास राज्य (अब तमिलनाडु) के पूर्व मुख्यमंत्री कामराज कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में गांधी से मतभेदों के चलते कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। कामराज का जन्म 1903 में हुआ था और उनका निधन 1975 में हुआ। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ''के. कामराज को उनकी जयंती पर मेरी श्रद्धांजलि। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अमिट योगदान दिया और एक

तत्कालीन मद्रास राज्य (अब तमिलनाडु) के पूर्व मुख्यमंत्री कामराज कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में गांधी से मतभेदों के चलते कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। कामराज का जन्म 1903 में हुआ था और उनका निधन 1975 में हुआ। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ''के. कामराज को उनकी जयंती पर मेरी श्रद्धांजलि।

करूणमयी प्रशासक के रूप में उन्होंने छाप छोड़ी।'' मोदी ने कहा, ''उन्होंने गरीबी मिटाने और लोगों के कष्ट कम करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना ध्यान केंद्रित किया।

एकनाथ शिंदे ने दूर कीं बाधाएं, अब फास्ट ट्रैक पर आएगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम; अब तक पिछड़ा था महाराष्ट्र

मुंबई। गुजरात के अहमदाबाद से मुंबई की दूरी को कम करने वाले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर अब महाराष्ट्र में भी काम तेज होने की उम्मीद है। एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली सरकार ने इस प्रोजेक्ट की बाधाओं को दूर करने का फैसला लिया है, जिससे बुलेट परियोजना के फास्ट ट्रैक पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पूर्व एमडी सतीश अग्निहोत्री ने इस संबंध में महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को पत्र भी लिखा था। इसमें उन्होंने कुल 16 मुद्दे गिनाए थे, जिन्हें दूर करने पर बुलेट ट्रेन परियोजना के काम में तेजी आ सकती है। इनमें से कई मसलों को एकनाथ शिंदे की लीडरशिप वाली सरकार ने दूर कर दिया है।

जापान की कंपनी ने भी देरी पर जताई थी चिंता

रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की ओर से स्टेज-1 फॉरेस्ट क्लियरेंस भी दे दिया गया है। अग्निहोत्री ने 7 जुलाई को ही लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि जापानी एजेंसी की ओर से दबाव है कि महाराष्ट्र में काम पिछड़ रहा है। इस परियोजना के संबंध में टेंडर्स को लगातार स्थगित करना पड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट पर कुल 1.08 लाख करोड़ रुपये की लागत आ रही है, जिसमें 81 फीसदी की फंडिंग जापान द्वारा ही की जा रही है। अग्निहोत्री के पत्र पर ऐक्शन लेते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को मीटिंग की थी और उन मसलों को दूर करने का फैसला लिया, जिनके चलते परियोजना में देरी हो रही है।

CBI ने हथियार लाइसेंस रिश्वत मामले में IAS अधिकारी राजेश को किया गिरफ्तार

अहमदाबाद। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने अपात्र लोगों को हथियार लाइसेंस देने के बदले रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी के. राजेश को बृहस्पतिवार को 18 जुलाई तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। अहमदाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश वी. बी. परमार ने सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव के. राजेश को गिरफ्तारी के एक दिन बाद केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। अधिकारियों के मुताबिक गुजरात कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश को पूछताछ के लिए सीबीआई के अहमदाबाद स्थित कार्यालय में बुलाया गया था। पूछताछ में कथित तौर पर सहयोग नहीं करने के बाद बुधवार को आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेश के खिलाफ मई में मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों के अनुसार आरोप है कि जब राजेश सुरेंद्रनगर जिले के जिलाधिकारी थे, तब उन्होंने जमीन के सौदे में और अपात्र लोगों को हथियार लाइसेंस मंजूर करने में रिश्वत ली थी। सीबीआई ने

अहमदाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश वी. बी. परमार ने सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव के. राजेश को गिरफ्तारी के एक दिन बाद केंद्रीय एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

इस सिलसिले में मई में मोहम्मद रफीक मेनन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था जो कथित तौर पर अधिकारी के एजेंट के रूप में काम करता था। अपात्र लोगों को हथियारों का लाइसेंस देने के अलावा राजेश पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपात्र लोगों के नाम पर सरकारी जमीन के आवंटन और अतिक्रमण की गयी सरकारी जमीन को नियमित करने के लिए भी रिश्वत ली थी।

कांवड़ यात्रा पर कट्टरपंथियों के हमले का खतरा, यूपी, मप्र समेत इन राज्यों के लिए गृह मंत्रालय का अलर्ट

नई दिल्ली। सावन माह शुरू होते ही यूपी समेत देशभर में कांवड़ यात्रा का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच, इन यात्राओं को कट्टरपंथियों या आतंकियों द्वारा निशाना बनाए जाने का अंदेशा है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सतर्क रहने और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। सावन लगते ही गुरुवार से देश की पवित्र नदियों से शिव मंदिरों में जल अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्रियों के जत्थे रवाना हो गए हैं। यूपी समेत देश के अनेक राज्यों में बड़े पैमाने पर ये यात्राएं निकाली जाती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे कांवड़ियों की सुरक्षा बढ़ाने के तत्काल इंतजाम करें। सूत्रों ने कहा कि गुप्तचर ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों का अलर्ट किया है। इन राज्यों को कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की सलाह दी है।

रेलवे बोर्ड को भी किया आगाह

गृह मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को भी कांवड़

यात्रियों पर हमले के खतरे को देखते हुए ट्रेनों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। एडवाइजरी के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए।

एक करोड़ कांवड़िये पहुंचेंगे हरिद्वार

कोरोना के कारण दो साल बाद हो रही कांवड़ यात्रा

बता दें, कोरोना महामारी के कारण बीते दो साल बाद इस साल कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। करीब एक माह चलने वाले मेले के दौरान कम से कम चार करोड़ कांवड़िये हरिद्वार और पड़ोसी ऋषिकेश में पवित्र गंगा नदी का पानी लेने पहुंचेंगे।

हरिद्वार और ऋषिकेश में खास सतर्कता

सावन माह में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों के कांवड़िये पैदल गंगाजल लेने हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं और अपने घर लौटकर मंदिरों में भगवान शिव को चढ़ाते हैं। इसलिए इन दोनों शहरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की आशंका को देखते हुए सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है।

दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक रेस्तरां में लगी भीषण आग

फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची

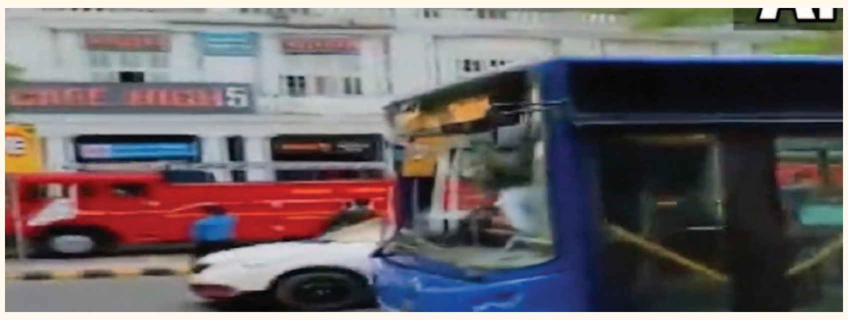

नयी दिल्ली। मध्य दिल्ली में कनॉट प्लेस इलाके के एक रेस्तरां में शुक्रवार सुबह आग लग गई। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कनॉट प्लेस में बाहरी सर्कल के 'हाई-फाई' रेस्तरां में आग लगने की सूचना तड़के पांच बजकर 32 मिनट पर मिली। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर छह दमकल गाड़ियों को भेजा गया और आग पर सुबह छह बजकर 35 मिनट पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है।

वैक्सीन का महा अभियान शुरू, 75 दिनों तक 18+ आबादी को लगेंगे मुफ्त बूस्टर डोज

नई दिल्ली। कोरोनावायरस के खिलाफ जंग में भारत ने एक और अहम कदम उठाया है। शुक्रवार से देश में पात्र वयस्क आबादी को मुफ्त में एहतियाती खुराक लगाने का अभियान शुरू हो रहा है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने बताया है कि कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से 30 सितंबर, 2022 तक 75 दिनों के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। खास बात है कि यह विशेष टीकाकरण अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य सभी वयस्क आबादी को सरकारी केंद्रों पर मुफ्त बूस्टर डोज देना है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में नोडल अधिकारी डॉक्टर विजय पाणीग्रही ने बताया, यह आज से शुरी हो रहा है और अगले 75 दिनों तक जारी रहेगी। गहम 18 से 59 साल के सभी नागरिकों के टीकाकरण की कोशिश कर रहे हैं।

मिशन मोड में चलेगा अभियान

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से गुरुवार दी गई जानकारी के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से इस अभियान को मिशन मोड में चलाने के लिए कहा गया है। साथ ही सरकार ने इस दौरान पहले से ज्यादा कोविड टीकाकरण शिविरों की बात कही है। विज्ञप्ति के अनुसार, एहतियाती खुराक के लिए पात्र लोगों में 18 वर्ष या इससे अधिक के सभी व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने दूसरी खुराक लगाने की तारीख के बाद 6 महीने (या 26 सप्ताह) का समय पूरा कर लिया है।

राखी सावंत को लग रहा है डर, कहा- मुझे छुड़ाने के लिए हिंदुस्तान का सारा पैसा मोदी जी को श्रीलंका को देना पड़ेगा...

यात्राओं पर होगा खास ध्यान

इस अभियान के तहत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यात्राओं पर खास ध्यान देने की बात कही है। मंत्रालय के अनुसार, चार धाम यात्रा (उत्तराखंड), अमरनाथ यात्रा (जम्मू और कश्मीर), कांवर यात्रा (उत्तर-भारत के सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों) के साथ-साथ प्रमुख मेलों और जन समूहों के मार्गों पर विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित करने की सलाह दी गई।

इलेक्ट्रिक वाहनों से भी पूरी तरह नहीं लगेगी वायु प्रदूषण पर लगाम

नई दिल्ली। देश और दुनिया में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहन) की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस बीच एक अध्ययन में पता चला है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को दौड़ाकर अभी हम अपने देश में सिर्फ 20 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन ही कम कर पाएंगे, क्योंकि देश में 70 प्रतिशत बिजली कोयले से उत्पादित की जा रही है। सोसायटी आफ रेयर अर्थ के मुताबिक, एक इलेक्ट्रिक कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले 57 किलो कच्चे माल (आठ किलो लीथियम, 35 किलो निकिल, 14 किलो कोबाल्ट) को जमीन से निकालने में 4,275 किलो एसिड कचरा एवं 57 किलो रेडियोएक्ट्रिव अवशेष पैदा होते हैं। आस्ट्रेलिया में हुआ एक शोध कहता है कि अभी दुनिया में ई-वाहनों से हर साल 3300 टन लीथियम कचरा निकल रहा है जिसमें से दो प्रतिशत हिस्सा ही रिसाइकिल हो पाता है, शेष 98 प्रतिशत प्रदूषण फैलाता है। लीथियम सबसे हल्का धातु है। यह बहुत आसानी से इलेक्ट्रान छोड़ता है। इसी कारण ई-वाहन के लिए बैटरी बनाने में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लीथियम युक्त बैटरियां इस्तेमाल के बाद कचरे में फेंक दी जाती हैं। कई बार पानी के संपर्क में आने से इनमें आग लग जाती है। अमेरिका के पैसिफिक नार्थवेस्ट में जून 2017 से दिसंबर 2020 तक इन बैटरियों से आग लगने की 124 घटनाएं हुईं। एक इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में नौ टन कार्बन निकलता है, जबकि पेट्रोल चालित वाहन बनाने में 5.6 टन कार्बन निकलता है। एक

इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में 13,500 लीटर पानी लगता है, जबकि एक पेट्रोल चालित कार में करीब चार हजार लीटर पानी लगता है। यदि इलेक्ट्रिक वाहन को कोयले से बनी बिजली से चार्ज करें तो डेढ़ लाख किमी चलने पर उससे पेट्रोल कार के मुकाबले 20 प्रतिशत ही कम कार्बन निकलेगा। जाहिर है इलेक्ट्रिक वाहनों को उसी देश में चलाया जाना ज्यादा बेहतर हो सकता है, जहां बिजली कोयले के मुकाबले अक्षय ऊर्जा से ज्यादा उत्पादित की जाती हो। मौजूदा समय में हमारे देश में अधिकांश बिजली कोयले से उत्पादित होती है। इंटरनेशनल काउंसिल आन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के मुताबिक, यूरोप के देशों में 60 प्रतिशत तक बिजली अक्षय ऊर्जा से बनती है। लिहाजा वहां अभी एक इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल चालित कार के मुकाबले 69 प्रतिशत कम कार्बन पैदा करती है। देखा जाए तो दुनिया में करीब दो सौ करोड़ वाहन हैं। इनमें एक करोड़ ही इलेक्ट्रिक

यदि इलेक्ट्रिक वाहन को कोयले से बनी बिजली से चार्ज करें तो डेढ़ लाख किमी चलने पर उससे पेट्रोल कार के मुकाबले 20 प्रतिशत ही कम कार्बन निकलेगा।

हैं। अगर सभी को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाए तो उन्हें बनाने में जो एसिड कचरा निकलेगा, उसके निस्तारण के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त साधन ही नहीं हैं। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाकर, निजी कारें घटाकर और बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाकर ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर सकते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

मुफ्त का रक्षा-कवच

अजीब विडंबना ही है कि देश-दुनिया में रह-रहकर सामने आ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बावजूद हम मान बैठे हैं कि कोरोना वायरस वापस वुहान लौट गया है। बचाव के एहतियाती उपाय मास्क, सुरक्षित दूरी व बार-बार हाथ धोने को बीते दिनों की बात बना चुके हैं। इसके बावजूद कि दुनिया के कई देश संक्रमण की गंभीर चुनौती से जूझ रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आने वाला उछाल इससे जुड़ी चिंता को दर्शाता रहता है। लेकिन फिर भी, देश में वैक्सीन की उपलब्धता के बावजूद लोग एहतियाती खुराक लेने में कोताही बरत रहे हैं। वैसे तो देश में इस साल दस जनवरी से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो चुकी थी। मकसद था कि यदि वैक्सीन से प्राप्त इम्युनिटी में कमी आती है और कोई नया वायरस आये तो बचाव हो सकता है। देश में साठ साल से अधिक के लोगों व अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को यह डोज मुफ्त लगायी जा रही थी। देश में साठ साल से अधिक के करीब पच्चीस फीसदी लोग बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। बताया जाता है कि बूस्टर डोज लगाने में देश की रफ्तार दुनिया में काफी धीमी है। लेकिन 18 से 59 साल के लोगों ने बूस्टर डोज को गंभीरता से नहीं लिया। देश में केवल एक फीसदी के करीब इस आयु वर्ग के लोगों ने ही एहतियाती खुराक ली। जो कि बेहद चिंता की बात इसलिए है कि सेहत से जुड़े मामलों में हम कितने गंभीर हैं। वह भी तब जब अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैग्जीन कह रही है कि भारत में एक नया वायरस सामने आया है जो हमारी प्राकृतिक व वैक्सीन से हासिल रोग प्रतिरोधक क्षमता को पछाड़ रहा है। दरअसल, अब तक 18 से 59 आयु वर्ग को मामूली कीमत चुकाकर बूस्टर डोज मिल रही थी, जिसके चलते लोगों ने इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखायी। यही वजह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 दिनों का विशेष अभियान चलाकर इस आयुवर्ग को मुफ्त बूस्टर डोज देने का फैसला लिया है।

उम्मीद की जानी चाहिए कि देश का लक्षित आयुवर्ग इस अवसर का लाभ उठायेगा और खुद व देश को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। सरकार की भी कोशिश है कि आजादी के अमृतकाल में 75 दिन तक लोगों के घर-घर जाकर टीकाकरण अभियान में भाग लेने की अपील की जाये। निश्चित रूप से यदि लोग सहयोग करेंगे तो कोरोना संक्रमण के खिलाफ उनके शरीर में एंटीबॉडी क्षमता बढ़ जायेगी। हमें नये वायरस बीए.2.75 की चुनौती को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो भारत में कई जगह पाया गया है। दरअसल कोरोना वायरस का यही वेरिएंट ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। जिसके बारे में चेताया जा रहा है कि इसे इंसान की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रोक पा रही है। जिससे दुनियाभर के वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में विश्वास किया जाना चाहिए कि बूस्टर डोज लगाने का कुछ फायदा जरूर होगा। हो सकता है कि नई चुनौती को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने 18 से 59 साल के आयुवर्ग के लिये बूस्टर डोज मुफ्त में लगाने का फैसला किया हो। हमें एक जिम्मेदार नागरिक का व्यवहार करते हुए बूस्टर डोज अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। साथ ही संक्रमण से बचाव के परंपरागत एहतियाती उपायों पर गंभीर व्यवहार करना चाहिए। नागरिकों को इस बात का अहसास होना चाहिए कि कोरोना वायरस कहीं जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ जीने का सलीका सीखना होगा। अपने अनुकूल वातावरण पाकर यह कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को अपना शिकार बनाता रहेगा। कालांतर अन्य मौसमी रोगों की तरह यह भी अपना असर दिखाता रहेगा। बहुत संभव है कि निकट भविष्य में कारगर दवाइयां उपलब्ध होने के बाद इस पर काबू पाया जा सकेगा। तब तक हमारी सावधानी और सतर्कता ही इसका उपचार होगा। बहुत संभव है कि बूस्टर डोज लगाने वाले लोगों को कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद ज्यादा परेशानी न हो, अस्पताल जाने की नौबत न आये।

विपक्ष की दयनीयता

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जब द्रौपदी मुर्मू को अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया था, तब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, और कम्युनिस्ट पातटयों जैसी विपक्षी एकता की तुरही बजाने वाली पातटयों को यह अनुमान नहीं था कि भाजपा का यह दांव उनकी कथित एकता की भुरभुराहटको इस तरह उजागर कर देगा। वैसे तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विपक्षी एकता का नेतृत्व वास्तव में कौन कर रहा

हैग फिर भी ममता बनर्जी की पहल को नेतृत्वकारी माना जाए तो ममता को इस समय भारी निराशा हो रही होगी कि बीजू जनता दल, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगू देशम, शिरोमणि अकाली दल जैसे राजग के बाहर के दल द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आए हैं और शिवसेना ने जिस तरह कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रुख के विरुद्ध भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में खड़े होने की घोषणा की है, उसने महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस और एनसीपी की संभावनाओं की जमीन हिला दी है। यहां दो बातें बहुत स्पष्ट हैं कि विपक्षी दलों के पास भाजपा का विरोध करने के नाम पर सिवाय विरोध के कोई साझा कार्यक्रम या साझी कार्यनीति नहीं है। दूसरा; यह कि द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी ने प्रमुख आदिवासी ताकतों के भाजपा विरोधी रुळख को बेहद कमजोर कर दिया है। यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे लोग विपक्षी एकता से पल्ला छुड़ाते नजर आ रहे हैं। आगामी लोक सभा चुनाव से पूर्व विपक्ष की नीतिगत असफलता और संगठनात्मक विफलता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाजपा की राजनीतिक शक्ति बढ़ रही है और 2024 के लोक सभा चुनाव में उसकी भावी विजय का पूर्वाभास भी दे रही है। भाजपा के विरुद्ध विपक्ष का इस तरह दयनीय स्थिति में आ जाना लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो मोदी के अंधविरोधी विपक्षी दल स्वयं ही हैं। विपक्षी दलों को समय रहते सबक लेना चाहिए और उन्हें एक झुंड के रूप में मोदी के विरोध में एकत्रित होने के बजाय नीतिगत और कार्यगत आपसी एकता स्थापित करनी चाहिएग जिससे उनके विरोध को राजनीतिक वैधता प्राप्त हो सके। और विपक्ष सचमुच एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सके।

चिंतन-मनन

कर्त्तव्य को बनाएं सर्वोपरि लक्ष्य

अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा- 'रामायण और महाभारत में क्या अंतर है?' विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी समझ के अनुसार उत्तर दिए।

अध्यापक को संतोष नहीं हुआ। एक विद्यार्थी ने अनुरोध किया- 'आप ही बताइए' अध्यापक बोला-रामायण और महाभारत में सबसे बड़ा अंतर है 'हक-हकूक' का। रामायण में राम ने अपना अधिकार छोड़ा, राज्य छोड़ा और चौदह वर्षों तक वन में जाकर रहे। वे चाहते तो अधिकार के लिए लड़ाई कर सकते थे। दशरथ उन्हें वन में नहीं भेजना चाहते थे। अयोध्या की जनता उनके वन-गमन से व्यथित थी। पर राम ने अपने कर्त्तव्य को अधिकार से ऊपर रखा। पिता के कहे का पालन उनके जीवन का महान आदर्श था।

महाभारत का संपूर्ण कथानक अधिकारों की लड़ाई का कथानक है। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। भाई-भाई के रिश्तों में जो गंध होती है, मिठास होती है, अपनापा होता है, उसका दर्शन ही वहां कहां होता है! पांडव सब कुछ जुए में हार गए। सब वादे पूरे कर वे लौटे तो दुर्योधन ने पांच गांव तो क्या, सूई की नोक के बराबर भूमि भी देने से मना कर दिया। ये दो उदाहरण हैं-हमारे सामने। प्रथम उदाहरण अपनेपन से भरे आत्मीय संबंधों का है। यह संबंधों की मधुरता व्यक्ति को कभी आत्मकेंद्रित नहीं होने देती। वह अपने बारे में नहीं सोचता; परिवार, समाज और देश के बारे में सोचता है। उसका अपना कोई स्वार्थ होता ही नहीं। पद-प्रतिष्ठा और सुख-सुविधा के संस्कारों से वह ऊपर उठ जाता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है, जो कर्त्तव्य को अपने जीवन का सवरेपरि लक्ष्य मानता है। वह संस्कृति सफल होती है जो कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों को जन्म देती है।

वह शताब्दी सफल होती है, जो कर्त्तव्य की धारा को सतत प्रवाही बनाकर जन-जन तक पहुंचाती है। वह परंपरा सफल होती है, जो कर्त्तव्य का बोध देती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि पूजा-प्रतिष्ठा, मान-सम्मान और सुख-सुविधा की अर्थहीन चिंता छोड़कर व्यक्ति अपने जीवन को कर्त्तव्य के लिए समर्पित कर दे।

बेहतर भविष्य का व्यावहारिक विचार

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

जनसँख्या नियंत्रण का संबन्ध विकास व संसाधनों से भी जुड़ा है। संसाधनों की भी एक सीमा होती है। जनसँख्या व संसाधनों के बीच संतुलन होना चाहिए। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों का अभाव होने लगता है। सबसे पहले इसका प्रतिकूल प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। जिस वस्तु का अभाव होता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। धनी वर्ग उसे खरीद सकता है। जबकि गरीबों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जनसँख्या की अनियंत्रित वृद्धि विकास में बाधक भी साबित हो सकती है। इससे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। लोगों के जीवन स्तर में कमी आती है।

भारत में जनसँख्या के स्थिरीकरण और संतुलन दोनों पर गंभीरता से विचार करना होगा। यह भविष्य के प्रति वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है। किन्तु इस गंभीर मसले को भी विपक्ष वोटबैंक नजरिये से देख रहा है। इसका मतलब है कि उसे केवल अपनी वर्तमान राजनीति की चिंता है, भावी पीढ़ी की उसे कोई परवाह नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसँख्या के स्थिरीकरण और संतुलन का विषय उठाया लेकिन प्रतिपक्ष ने इसे लोकतंत्र से जोड़ दिया। यह दिखाने का प्रयास किया गया जैसे लोकतंत्र की चिंता केवल उसे है। योगी आदित्यनाथ का कहना समाज विज्ञान के आधार पर बिल्कुल सही था। उनका कहना था कि किसी एक वर्ग की जनसँख्या में अप्रत्याशित वृद्धि अशांति को जन्म देती है।

भारत विविधताओं का देश है। यहां की जनसँख्या में संतुलन कायम रखना अपरिहार्य है। जिन्होंने योगी के इस कथन का विरोध किया है, उन्हें अपने शासनकाल में कैराना आदि कस्बों की दशा पर विचार करना चाहिए। यहां जनसँख्या में असंतुलन के दुष्परिणाम दिखाई देने लगे थे। तत्कालीन सरकार इसका समाधान करने में विफल थी क्योंकि यह उसके लिए वोटबैंक का विषय था। कश्मीर घाटी, पश्चिम बंगाल, केरल के अनेक इलाकों में यही दशा रही है। आश्चर्य यह कि विपक्ष इस विषम स्थिति को जानबूझकर कर देखना नहीं चाहता।

योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बढ़ती जनसंख्या समाज में व्याप्त असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल है। समुन्नत समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिक शर्त है। जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लेना चाहिए। जनसँख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूकता प्रयासों के क्रम में स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाये जाने का अभिनव प्रस्ताव है। डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजातों किशोरों और वृद्धजनों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था की भी बात है। सभी समुदायों में जन सांख्यकीय संतुलन बनाये रखने, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता, समुचित पोषण पर भी जोर दिया गया। जिन देशों की जनसंख्या अधिक होती है, वहां जनसांख्यकीय असंतुलन घातक होता है। इससे धार्मिक जनसांख्यिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होने चाहिए।

विपक्ष ने राष्ट्रीय महत्त्व के इस विषय को भी राजनीति के हवाले कर दिया। ट्वीट किया गया कि अराजकता आबादी से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से पैदा होती है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास दशकों से चल रहे है। सरकार द्वारा संचालित अभियान के देश ने दो स्वरूप देखे हैं। आपातकाल के दौरान जनसँख्या नियंत्रण नीति जोर जबरदस्ती पर आधारित थी। लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद इसे नकार दिया गया। शेष अवधि में प्रचार व सहायता के माध्यम से जनसँख्या नियंत्रण का अभियान चलाया गया लेकिन इसका भी पर्याप्त लाभ नहीं हुआ।

जाहिर है कि यह विषय दशकों पुराना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस विषय को उठाया था। जनसँख्या नियंत्रण के दोनों स्वरूपों की विफलता सामने है। इसलिए नए रास्ते की तलाश का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात यह विषय पुराना है, लेकिन समाधान का तरीका अवश्य नया है। आपातकाल के दौरान ही संविधान संशोधन पारित किया गया था। इसके द्वारा समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय जोड़ा गया था। ऐसे में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा इससे संबंधित अधिनियम बनाना असंवैधानिक नहीं हो सकता। करीब दो दशक पहले भी संविधान समीक्षा आयोग ने केंद्र सरकार को इससे संबंधित निर्देश दिया था। कहा गया कि वह जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून बनाएं। इस समय दर्ज याचिका में संविधान समीक्षा योग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही गई है।

जनसँख्या नियंत्रण का संबन्ध विकास व संसाधनों से भी जुड़ा है। संसाधनों की भी एक सीमा होती है। जनसँख्या व संसाधनों के बीच संतुलन होना चाहिए। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों का अभाव होने लगता है। सबसे पहले इसका प्रतिकूल प्रभाव गरीबों पर पड़ता है। जिस वस्तु का अभाव होता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। धनी वर्ग उसे खरीद सकता है। जबकि गरीबों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जनसँख्या की अनियंत्रित वृद्धि विकास में बाधक भी साबित हो सकती है। इससे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। लोगों के जीवन स्तर में कमी आती है।

भारत के लिए यह स्थिति विशेष चिंता का विषय है। भारत के पास विश्व की मात्र दो प्रतिशत भूभाग है। जबकि यहां पर विश्व की 20 प्रतिशत जनसँख्या निवास करती है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में एक सौ पैंतीस करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ वर्षों में चीन भी भारत से पीछे हो जाएगा। जनसँख्या के मामले में भारत सबसे बड़ा देश हो जाएगा। जिस गति से जनसँख्या बढ़ रही है, उसके अनुरूप संसाधनों की व्यवस्था संभव नहीं है। राजनीतिक दल चाहे जो दावा करें, वह संसाधनों का सृजन नहीं कर सकते। जो लोग जनसँख्या नियंत्रण का विरोध करते हैं, उन्हें संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के संबन्ध में भी विचार व्यक्त करना चाहिए। जनसंख्या का स्थिरीकरण होना अपरिहार्य है। 1991 से 2021 के बीच उत्तर प्रदेश की आबादी एक सौ बीस प्रतिशत बढ़ी थी। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। तब प्रदेश की आबादी 13 करोड़ थी। अब यह बढ़कर 25 करोड़ से अधिक हो गई है। यह माना गया कि बढ़ती जनसंख्या से विकास व संसाधनों से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस आधार पर समाज में दो वर्ग है। एक वर्ग ने स्वेच्छा से जनसँख्या नियंत्रण को स्वीकार किया है। यह उनका समाज व देश के प्रति सहयोग भी है। दूसरे वर्ग ने जनसँख्या नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया। इस कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। सहयोग करने वालों को प्रोत्साहन देना चाहिए। जबकि ऐसा ना करने वालों को उन्हीं सीमित संसाधनों से सुविधा प्रदान करते रहने का औचित्य नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से अलग है। सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध हो जो जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग कर रहे हैं। विशाल जनसंख्या एक संसाधन तभी होता है जब ईज ऑफ लिविंग का स्तर ठीक हो। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि था कि मानव की आबादी को सौ करोड़ तक होने में लाखों वर्ष लगे थे लेकिन सौ से पांच सौ करोड़ होने में दो शताब्दी भी नहीं लगी। इस वर्ष के अंत तक विश्व की आबादी आठ सौ करोड़ होने की सम्भावना है। जनसंख्या स्थिरीकरण में जागरुकता का सबसे अधिक महत्व है। यह जागरुकता केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी ही नहीं है। नगर विकास,ग्राम्य विकास, शिक्षा आदि विभागों को भी इससे जुड़ना होगा। हमने मस्तिष्क ज्वर के नियंत्रण में अन्तर्विभागीय समन्वय के महत्व को देखा है। जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सफलतापूर्वक संचालित करने की आवश्यकता है लेकिन जनसांख्यिकीय असंतुलन नहीं होना चाहिए। योगी ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और जो मूल निवासी हों उन लोगों की आबादी को जागरूकता और इंफोर्समेण्ट से नियंत्रित कर दिया जाए। स्पष्ट है कि जनसँख्या पर योगी के विचार देश के व्यापक हित में हैं। उनके लिए यह विषय राजनीति या चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है।

विचार मंथन

राजपक्षे की अदूरदर्शिता

सिद्धार्थ शंकर

श्रीलंका में आर्थिक तबाही के बाद भड़के जन विद्रोह के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे बुधवार तड़के कोलंबो से भाग निकले। श्रीलंका की वायुसेना के विमान से अपनी पत्नी व अंगरक्षकों के साथ मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए। आज ही वे इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन उसके पहले वह देश छोड़कर चले गए। श्रीलंका के पीएम कार्यालय ने भी पुष्टि की है कि राजपक्षे देश छोड़कर चले गए हैं। गोटबाया के श्रीलंका छोडऩे के बाद बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। श्रीलंका में राष्ट्रपति का वही ओहदा या अधिकार होता है जो भारत में प्रधानमंत्री का। भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था संभालने में विफल रहने के कारण श्रीलंका में कई महीनों से बवाल जारी था। बीते दिनों जनता सड़कों पर उतर आई और सैकड़ों लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। उसके बाद से राजपक्षे लापता थे। इसी बीच उन्होंने एलान किया था कि वे 13 जुलाई को पद छोड़ देंगे। खबर है मिक राजपक्षे के भाई व पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने भी श्रीलंका छोड़ दिया है। 71 साल के बासिल को श्रीलंका की आर्थिक बदहाली का बड़ा जिम्मेदार बताया जा रहा है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने श्रीलंका की संसद स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे दोनों को सूचित किया था कि वे 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। स्पीकर अभयवर्धने को बुधवार को राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की घोषणा करने की उम्मीद थी। इस बीच, श्रीलंका के राजनीतिक दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके बाद दिवालिया हो चुके देश को अराजकता से बचाने के लिए 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति के चुनाव का फैसला किया है। अब श्रीलंका में भविष्य में कुछ भी हो, मगर अभी तो दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में दर्ज हो गया कि पहली बार निहत्थी जनता ने सड़कों पर आकर, विधिवत एक निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया और प्रधानमंत्री आवास को फूंक डाला। श्रीलंका की जनता ने पिछले मई में देश के सर्वशक्तिमान राजपक्षे परिवार के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को जान बचाकर भागने और नौसैनिक अड्डे पर शरण लेने को मजबूर कर दिया था। महिंदा की हैसियत अपने भाई, लगभग निवर्तमान हो चुके राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने ही राष्ट्रपति के नाते मई, 2009 में तमिल इलाकों को तहस-नहस करवाने के बाद लगभग ढाई दशक से चल रहे गृहयुद्ध को खत्म करवाया था। राजपक्षे परिवार ने तमिलों के पराभव को सिंहल बहुसंख्यकवाद के वर्चस्व की स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया था। राजपक्षे परिवार की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के शीर्ष चार पदों पर परिवार के लोग ही थे; इसके अलावा नौकरशाही, सेना और अन्य पदों पर भी इसी खानदान के लोग काबिज थे। सत्ता के अहंकार ने राजपक्षे परिवार को जनता के गुस्से का अहसास नहीं होने दिया। गोटबाया ने हिसाब लगाया कि दूसरे परिवार के रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाकर संकट पर काबू पाया जा सकता है। इस तरह सर्जरी के केस को पेनकिलर से ठीक करने की कोशिश होती रही। लेकिन रोजमर्रा का संकट बढ़ता रहा। पेट्रोल-डीजल, खाने-पीने की चीजों और दवाओं की कमी ने आम आदमी की दुश्वारियों को असहनीय बना दिया। आज यह संकट पूरी दुनिया में श्रीलंका की जगहंसाई का कारण बन गया है।

प. बंगाल

चिंता का सबब बनता बारिश के पैटर्न में आ रहा बदलाव

योगेश कुमार गोयल

मानसून की शुरुआत से ही देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, बाढ़, बादल फटने, बिजली गिरने और भू-स्खलन से तबाही का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर आसमानी आफत टूट रही है तो देश के कई इलाके बाढ़ के कहर से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। असम के बाद गुजरात तथा महाराष्ट्र बाढ़ के प्रकोप से त्रस्त हैं, जहां अबतक काफी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी। देशभर की कई नदियां और जलाशय उफान पर हैं। हालांकि उत्तर भारत के कई इलाके मानसून की बारिश के लिए अब तक तरस रहे हैं।

कमोबेश हर साल मानसून के दौरान विभिन्न राज्यों में अब इसी प्रकार का नजारा देखा जाने लगा है। नि-संदेह यह सब पर्यावरण असंतुलन का ही दुष्परिणाम है, जिसके कारण मानसून से होती तबाही की तीव्रता साल दर साल बढ़ रही है। मानसून का मिजाज इस कदर बदल रहा है कि जहां मानसून के दौरान महीने के अधिकांश दिन सूखे निकल जाते हैं, वहीं कुछेक दिनों में ही इतनी बारिश हो जाती है कि लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती हैं। दरअसल वर्षा के पैटर्न में ऐसा बदलाव नजर आने लगा है कि बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है, जो प्राय: भारी तबाही का कारण बनता है।

मानसून प्रकृति प्रदत्त ऐसा खुशनुमा मौसम है, भीषण गर्मी झेलने के बाद जिसकी बूंदों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। यह ऐसा मौसम है, जब प्रकृति हमें भरपूर पानी देती है किन्तु पानी की कमी से बुरी तरह जूझते रहने के बावजूद हम इस पानी को सहेजने का कारगर इंतजाम नहीं करते और बारिश का पानी व्यर्थ बहकर समुद्रों में समा जाता है। हालांकि एक समय था, जब हर कहीं बड़े-बड़े तालाब और गहरे-गहरे कुएं होते थे और पानी अपने आप धीरे-धीरे उनमें समा जाता था, जिससे भूजल स्तर भी बढ़ता था लेकिन अब विकास की अंधी दौड़ में तालाबों की जगह ऊंची-ऊंची इमारतों ने ले ली है। शहर कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, अधिकांश जगहों पर कुओं को मिट्टी डालकर भर दिया गया है।

दरअसल हमारी फितरत कुछ ऐसी हो गई है कि हम मानसून का भरपूर आनंद तो लेना चाहते हैं किन्तु इस मौसम में किसी भी छोटी-बड़ी आपदा के उत्पन्न होने की प्रबल आशंकाओं के बावजूद उससे निपटने की तैयारियां नहीं करते। इसीलिए बदइंतजामी और साथ प्रकृति के बदले मिजाज के कारण अब प्रतिवर्ष प्रचण्ड गर्मी के बाद बारिश रूपी राहत को देशभर में आफत में बदलते देर नहीं लगती। तब मानसून को लेकर हमारा सारा उत्साह छू-मंतर हो जाता है।

हालांकि 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग' का शोर तो सालभर बहुत सुनते हैं लेकिन ऐसी योजनाएं सिरे कम ही चढ़ती हैं। इन्हीं नाकारा व्यवस्थाओं के चलते चंद घंटों की मूसलाधार बारिश में ही दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद, बेंगलुरू जैसे बड़े-बड़े शहरों में भी सड़कें दरिया बन जाती हैं और जल-प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह कोई इसी साल की बात नहीं है बल्कि हर साल यही नजारा सामने आता है लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसे पुख्ता इंतजाम कभी नहीं किए जाते, जिससे बारिश के पानी का संचयन किया जा सके और ऐसी समस्याओं से निजात मिले।

दरअसल हमारी व्यवस्था का काला सच यही है कि न कहीं कोई जवाबदेह नजर आता है और न ही कहीं कोई जवाबदेही तय करने वाला तंत्र दिखता है। हर प्राकृतिक आपदा के समक्ष उससे बचाव की हमारी समस्त व्यवस्था ताश के पत्तों की भांति ढह जाती है। ऐसी आपदाओं से बचाव तो दूर की कौड़ी है, हम तो मानसून में सामान्य वर्षा होने पर भी बारिश के पानी की निकासी के मामले में साल दर साल फेल साबित हो रहे हैं। देशभर के लगभग तमाम राज्यों में प्रशासन के पास पर्याप्त बजट के बावजूद प्रतिवर्ष छोटे-बड़े नालों की सफाई का काम मानसून से पहले अधूरा रह जाता है, जिसके चलते ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं। अनेक बार ऐसे तथ्य सामने आ चुके हैं, जिनसे पता चलता रहा है कि मानूसन की शुरूआत से पहले ही करोड़ों रुपये का घपला करते हुए केवल कागजों में ही नालों की सफाई का काम पूरा कर दिया जाता है। कई जगहों पर मानसून से पहले नालों की सफाई की भी जाती है तो उस दौरान सैंकड़ों मीट्रिक टन सिल्ट निकालकर उसे नाले के करीब ही छोड़ दिया जाता है, जो तेज बारिश के दौरान दोबारा बहकर नाले में चली जाती है और थोड़ी सी बारिश में ही ये नाले उफनते लगते हैं।

बारिश के कारण बाढ़, भू-स्खलन जैसी आपदाओं को लेकर हम जी भरकर प्रकृति को तो कोसते हैं किन्तु यह समझने का प्रयास नहीं करते कि मानसून की जो बारिश हमारे लिए प्रकृति का वरदान होनी चाहिए, वही बारिश अब हर साल बड़ी आपदा के रूप में तबाही बनकर क्यों सामने आती है? अति वर्षा और बाढ़ की स्थिति के लिए जलवायु परिवर्तन के अलावा विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, नदियों में होता अवैध खनन इत्यादि भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, जिससे मानसून प्रभावित होने के साथ-साथ भू-क्षरण और नदियों द्वारा कटाव की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते तबाही के मामले बढ़ने लगे हैं।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर चिकित्सक के नुस्खे के साथ बेचनी होंगी आयुर्वेदिक दवाएं, जारी हुए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स संस्थाओं से कहा है कि वह आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाओं को पंजीकृत चिकित्सक या वैध के नुस्खे पर ही बेच सकते हैं।इसके तहत वह दवाएं शामिल हैं, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक

रूल्स, 1945 की अनुसूची ई (1) में सूचीबद्ध सामग्री में शामिल हैं।इसमें आयुर्वेदिक (सिद्ध सहित) और यूनानी चिकित्सा पद्धति के तहत भांग, चरस, अफीम सरीखे पदार्थों से बनने वाली दवाएं आती हैं। जिसमें ज्यादातर दर्द निवारक, शक्तिवर्धक और असाध्य रोगों की दवाएं शामिल हैं।

लिहाजा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सलाह दी गई है कि ऐसी दवाओं की बिक्री एक पंजीकृत आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी चिकित्सक के वैध नुस्खे के बाद ही बेची जा सकेगी। इन दवाओं के बिना चिकित्सक की सलाह के इस्तेमाल से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं।इसलिए सीसीपीए ने यह सलाह जारी की है। साथ ही दवा के पैकेट पर हिंदी और अंग्रेजी में निर्देश या सावधानी अंकित करने को कहा है।

सीतारमण बोलीं- वैश्विक न्यूनतम कर समझौते में विकासशील देशों के हितों का ध्यान रखे जी20

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी20 देशों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि विकासशील देशों को जी20 में प्रस्तावित वैश्विक न्यूनतम कर सौदे के किसी भी 'गैर अपेक्षित परिणामों' से बचाया जाए। वित्तमंत्री ने कहा है कि एक निष्पक्ष और समावेशी कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी त्र20 समावेशी ढांचे के सदस्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए

प्रस्तावित सौदे को अंतिम रूप देने में सक्रिय रूप से भाग लें साथ ही इस समझौते के तहत विकासशील देशों के लिए 'सार्थक राजस्व' का प्रावधान भी किया जाना चाहिए।

आपको बता दें कि भारत सहित कुल 130 देशों ने पिछले साल जुलाई में वैश्विक कर मानदंडों में बदलाव के लिए सहमति व्यक्त की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां भी काम करती हैं वहां न्यूनतम 15 प्रतिशत की दर से करों का भुगतान करें। वित्त मंत्रालय की ओर से तब कहा गया था कि लाभ आवंटन में हिस्सेदारी और कर नियमों के दायरे सहित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया जाना बाकी है और प्रस्ताव के तकनीकी विवरण पर काम करने के बाद एक आम सहमति के आधार पर समझौता किया जाएगा।

अमेरिकी में बेरोजगारी लाभ का दावा करने वालों की संख्या आठ माह के उच्चस्तर पर

वाशिंगटनः अमेरिका में बेरोजगारी लाभ के लिए दावा करने वालों की संख्या पिछले सप्ताह बढ़कर करीब आठ महीने के उच्चस्तर पर पहुंच गई। हालांकि, बेरोजगारी लाभ उठाने वाले लोगों की कुल संख्या कम हुई है। अमेरिका के श्रम विभाग ने बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन करने वालों की संख्या नौ जुलाई को समाप्त सप्ताह में 9,000 बढ़कर 2,44,000 पर पहुंच गई। इससे एक सप्ताह पहले यह संख्या 235,000 थी। पहली बार बेरोजगारी लाभ के लिए आवेदन आमतौर पर नौकरियों में छंटनी को दर्शाते हैं।

अनाज, बिजली, पेट्रोल सस्ता होने से घटी थोक महंगाई, पर 15वें माह भी 10 फीसदी से ज्यादा

नई दिल्ली। अनाज, गेहूं, प्याज, पेट्रोल, बिजली और खनिज की कीमतों में गिरावट से जून, 2022 में थोक महंगाई के मोर्चे पर राहत मिली है। इसके साथ ही थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित महंगाई के पिछले तीन महीने से बढ़ने का चलन जून में बंद हो गया। फिर भी यह अप्रैल, 2021 से लगातार 15वें महीने 10 फीसदी से ऊंची बनी हुई है।

सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, खनिज और मूल धातु के दाम में मासिक आधार पर भले ही तेज सुधार हुआ है, लेकिन खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में तेजी बनी हुई है। जून में खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़कर 14.39 फीसदी पहुंच गई, जो मई, 2022 में 12.34 फीसदी रही थी। रेटिंग एजेंसी इक्रा का कहना है कि वैश्विक स्तर पर मंदी आने की आशंका बढ़ने और कमोडिटी की कीमतों में नरमी से खनिज

एवं मूल धातु सस्ते हुए हैं। इससे थोक महंगाई के मोर्चे पर राहत मिली है। लेकिन, फल, सब्जियों, आलू के दाम बढ़ने की वजह से डब्ल्यूपीआई महंगाई अब भी उच्च स्तर पर बनी हुई है।

मार्च तक पांच फीसदी रह जाएगी खुदरा महंगाई

एसबीआई लगातार बढ़ रही खुदरा महंगाई अगले साल मार्च तक 2 फीसदी घटकर 5 फीसदी के स्तर पर आ सकती है। जून, 2022 में यह मामूली घटकर 7.01 फीसदी पर आ गई। एसबीआई ने रिपोर्ट में कहा कि देश में खुदरा महंगाई दर लगातार छठे महीने 6 फीसदी से ऊपर रही है। हालांकि, पिछले दो महीने में सरकार और आरबीआई की ओर से उठाए गए कदमों से महंगाई के मोर्चे पर राहत मिली है। इन कदमों में पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती, खाद्य निर्यात पर प्रतिबंध शामिल हैं। मॉनसून बेहतर होने और आपूर्ति पक्ष में सुधार से आने वाले समय में महंगाईसे राहत मिल सकती है।?

एसबीआई ने कहा कि वैश्विक मंदी आने की फिलहाल 20 से 30 फीसदी ही आशंका है। इसकी प्रमुख वजह बढ़ती महंगाई और आक्रामक तरीके से बढ़ाई जा रही ब्याज दरें हैं। अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक गतिरोध बना रह सकता है।

चालू तिमाही में भी ऊंचे रहेंगे कोयले के दाम

इक्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि मानसून के दौरान कोयले की आपूर्ति को लेकर आने वाली मुश्किलों को देखते हुए चालू तिमाही में भी घरेलू कोयले के दाम अधिक बने रह सकते हैं। मई में घरेलू स्तर पर कोयले की ई-नीलामी पर प्रीमियम 400 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गया। इसका मूल धातु कंपनियों के लागत ढांचे और मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

जुलाई में मिलेगी राहत...

इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कमोडिटी और ईंधन की कीमतों में नरमी आ रही है। घरेलू स्तर पर भी खाद्य वस्तुओं के दाम धीरे-धीरे घट रहे हैं। इसका ज्यादा असर अगले महीने आने वाले जुलाई के थोक महंगाई के आंकड़ों पर दिखेगा। उम्मीद है कि जुलाई में थोक महंगाई घटकर 13 फीसदी रह जाएगी।

निर्यात 23.5 फीसदी बढ़ा, व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 26.18 अरब डॉलर

नई दिल्ली। देश के वस्तुओं का निर्यात जून, 2022 में 23.52 फीसदी बढ़कर 40.13 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस दौरान आयात 57.55फीसदी बढ़कर 66.31 अरब डॉलर पहुंच गया।? आयात में वृद्धि से देश का व्यापार घाटा जून में 172.7फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 26.18 अरब डॉलर पहुंच गया। जून, 2021 में 9.60 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था।?

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल-जून तिमाही में निर्यात 24.51फीसदी बढ़कर 118.96 अरब डॉलर रहा।?आयात भी 49.47फीसदी बढ़कर 189.76 अरब डॉलर पहुंच गया। व्यापार घाटा 31.42 अरब डॉलर से बढ़कर 70.80 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

40.13 अरब डॉलर का निर्यात किया गया इस साल जून में

रत्न-आभूषण निर्यात 21.41 फीसदी बढ़ा

रत्न एवं आभूषण निर्यात जून में 21.41फीसदी बढ़कर 25,295 करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले इसी महीने में यह 20,835 करोड़ था। अप्रैल-जूनमें निर्यात 14.6 फीसदी बढ़ा है।?

कहीं से भी करा सकेंगे कार-मोबाइल रिपेयर, ग्राहक होंगे मजबूत

नई दिल्ली। अगली बार जब आप मोबाइल फोन, कार या इस तरह के सामान खरीदने जाएं तो हो सकता है कि आप उसकी मरम्मत या रिपेयर किसी और भी दुकान से करा सकते हैं। कंपनियों को इसके लिए ग्राहकों को उत्पादों का पूरा विवरण देना अनिवार्य होगा। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इस तरह की खरीदी गई सामान की मरम्मत का अधिकार ग्राहकों को देगा। इससे उपभोक्ता की मूल निर्माता पर मरम्मत की निर्भरता भी खत्म हो सकेगी। जारी मरम्मत का अधिकार देने का मकसद ग्राहकों को मजबूत बनाना है। इसके लिए एक समिति गठित की गई जो इस पर अंतिम फैसला लेगी।

कम दाम व तय समय में बनेगा सामान

नए ढांचे के जरिये सामान की उचित मूल्य और तय समय में मरम्मत हो जाएगी। इससे निर्माता कंपनियों पर दबाव बनेगा कि वह ऐसे सामान बनाए जो टिकाऊ हो। विभाग ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि कंपनियां ऐसे सामान बनाती हैं जो एक तय समय के बाद नहीं चलता है।

कई सामानों को चिह्नित किया गया

समिति की अध्यक्ष निधि खरे ने पहली ही बैठक में खेती उपकरणों, मोबाइल फोन, टेबलेट, उपभोक्ता समानों, मोटर वाहनों, उनके उपकरणों में सुधार और

उन्हें दुरुस्त करने के अधिकार को चिह्नित किया है। इस बैठक में बाहर से मरम्मत करने पर वारंटी के अधिकार खोने जैसे मसलों पर भी चर्चा की गई। साथ ही कंपनियों द्वारा कम समय तक चलने वाले उत्पादों के उत्पादन और मरम्मत में अक्सर देरी होती है।

ईडी ने एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण को किया गिरफ्तार, मुंबई के पूर्व सीपी पर भी केस

नई दिल्ली। ईडी ने एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें चार दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और एनएसई के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का केस दर्ज कराया है।

जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है उनमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय और एक समय में एनएसई के टॉप लेवल की अधिकारी रहीं चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के नाम हैं। आपको बता दें कि यह केस एनएसई के अफसरों की ओर से गलत तरीके से फोन टैपिंग कराने और स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की जासूसी से जुड़ा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन सभी के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के आपराधिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज

कराया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने भी आरोपियों के खिलाफ पिछले हफ्ते इससे जुड़े एक मामले में केस दर्ज किया था। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि नारायण और रामकृष्ण ने मुंबई सेवानिवृत्त पुलिस आयुक्त संजय पांडे की एक कंपनी को शेयर बाजार के कर्मचारियों के फोन कॉल को अवैध रूप से इंटरसेप्ट करने के काम में लगाया था। पहले सीबीआई और अब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी संजय पांडेय, उनकी दिल्ली स्थित कंपनी, एनएसई के पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्ण, रवि नारायण, कार्यकारी उपाध्यक्ष रवि वाराणसी और एनएसई के प्रेमाइसेज हेड महेश हल्दीपुर को अपने-अपने केस में आरोपित बनाया है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी को गुप्त निगरानी में कथित अनियमितताओं का पता चला जिसके बाद उसने गृह मंत्रालय (म्ण्) को इसकी सूचना दी उसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

सुराना ग्रुप के दो प्रमोटर समेत चार लोगों को भी ईडी ने किया गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर, ईडी ने एक अन्य मामले में चेन्नई के सुराना ग्रुप के दो प्रमोटर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी मनी लाउंड्रिंग से जुड़े 3986 करोड़ रुपये के बैंक लोन फ्रॉड मामले में की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश चंद्र सुराना और विजय राज सुराना जो सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुराना पावर लिमिटेड और सुराना कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी और प्रमोटर हैं और पी आनंद और आई प्रभाकरण शेल कंपनियों के डमी निदेशक हैं, उन्हें 12 जुलाई को हिरासत में लिया गया है।

निजी इस्तेमाल के लिए 5जी देना समान अवसर के खिलाफ, अदाणी समूह लगाए कई आरोप

नई दिल्ली। कंपनियों को निजी उपयोग के लिए सरकार की ओर से 5जी नेटवर्क का आवंटन किया जाना सबको समान अवसर दिए जाने के सिद्धांत के खिलाफ है। यह बड़ी टेक (प्रौद्योगिकी) कंपनियों को 5जी सेवाएं एवं समाधान देने को पिछले दरवाजे से प्रवेश देने जैसा मामला होगा।उद्योग संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा, दूरसंचार सेवा कंपनियों पर लगाए नियामकीय अनुपालन और शुल्क जैसा प्रावधान किए बिना निजी

टेक कंपनियों को 5जी स्पेक्ट्रम देने की तैयारी है। सरकार 26 जुलाई से स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करेगी।

अदाणी के शामिल होने पर सीओएआई ने उठाया सवाल

सीओएआई का यह बयान स्पेक्ट्रम की नीलामी में अदाणी कंपनी के शामिल होने के बाद आया है। अदाणी समूह 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी में शामिल होगा। वह स्पेक्ट्रम का उपयोग अपने कारोबार के लिए निजी नेटवर्क खड़ा करने में करेगा।

कपिल वाधवन ने नियमों का पालन किए बिना बांटे 400 करोड़, सीबीआई ने किया बड़ा खुलासा

नई दिल्ली। यस बैंक-डीएचएफएल केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ा खुलासा किया है। एजेंसी ने एक और चार्जशीट दाखिल कर दावा किया है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) की मिलीभगत वाले 36,614 करोड़ रुपये में कर्ज देने में नियमों का पालन न करने के तरीके बताए हैं। सीबीआई के मुताबिक, डीएचएफएल के प्रमुख कपिल वाधवन ने धोखाधड़ी मामले में सह-आरोपी संजय छाबड़िया की कंपनियों बिना नियमों का पालन किए 400 करोड़ रुपये का लोन मुहैया कराया। गौरतलब है कि यह यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रमोटर्स कपिल और धीरज वाधवान के खिलाफ सीबीआई की तीसरी चार्जशीट है। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में छाबड़िया को सह-आरोपी बनाया गया है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इसी हफ्ते की शुरुआत में इस चार्जशीट का संज्ञान लिया था। इसमें यस बैंक में रहते हुए राणा कपूर की तरफ

से मंजूर किए गए कर्जों और उनके सह-आरोपियों की कंपनियों तक पहुंचने की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि जनवरी और मई 2018 के बीच 316 करोड़ और 100 करोड़ रुपये के कर्ज रेडियस एस्टेट एंड डेवलपर्स और रेडियस एस्टेट प्रोजेक्ट्स को दिए गए। यह दोनों ही कंपनियां छाबड़िया की थी। इन कर्जों को कपिल वाधवन की तरफ से मंजूरी दी गई थी।

सीबीआई का कहना है कि वाधवन इन कर्जों की मंजूरी ईमेल के जरिए ही दे देते थे। न ही इसके लिए अप्रेजल और न ही कर्ज प्रक्रिया के नोट्स देखे जाते थे। चार्जशीट में कहा गया है कि कपिल और धीरज वाधवन ने राणा कपूर और संजय राजकुमार छाबड़िया के साथ मिलकर यस बैंक और डीएचएफएल को चूना लगाने की साजिश रची।

18 पैसे की गिरावट के साथ सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, देश में बढ़ेगी महंगाई, आयातकों को होगा घाटा

नई दिल्ली। विदेशी बाजारों में मजबूती के बीच भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। गुरुवार को भारतीय रुपये में 18 पैसे की गिरावट हुई। फारेक्स मार्केट में डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 79.9975 पर बंद हुई जबकि थोक मुद्रास्फीति लगातार 15 महीनों से जून तक दोहरे अंकों में रही।

विश्लेषकों ने कहा कि हालांकि, पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट से रुपये को राहत मिली है। भारतीय रुपया क्षेत्रीय मुद्राओं के बीच औसत प्रदर्शनकर्ता बन गया है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपये ने दिन की शुरुआत में मजबूत रुख के साथ 79.71 प्रति डॉलर पर की। कारोबार के दौरान रुपया 79.71 के उच्चतम स्तर तक गया और 79.99 रुपये के निचले स्तर तक आया। आखिर में रुपया पिछले बंद भाव के मुकाबले 18 पैसे की गिरावट के साथ 79.99 प्रति

डॉलर पर बंद हुआ।खनिजों की कीमतों में तेज गिरावट के कारण थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून में तीन महीने के निचले स्तर 15.18 प्रतिशत पर आ गई है, लेकिन खाद्य पदार्थों पर महंगाई बढ़ रही है। जून लगातार 15वां महीना है जब थोक महंगाई दर दहाई अंक में रही। पिछले महीने थोक महंगाई दर ने 15.88 फीसदी की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था। जून 2021 में थोक महंगाई दर 12.07 फीसदी थी।

इस बीच वित्त मंत्रालय ने कहा है कि महंगा आयात और कमजोर व्यापारिक निर्यात के कारण चालू वित्त वर्ष में भारत का चालू खाता घाटा बिगड़ने की आशंका है। सीएडी और बढ़ते एफपीआई की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, जनवरी 2022 से छह महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार में 34 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट आई है। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी मुद्रास्फीति 41 साल के उच्च स्तर पर है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट में जारी उतार-चढ़ाव के बीच डॉलर की मांग बढ़ती जा रही है। युद्ध कारण रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके कारण ही ट्रेडिंग के लिए डॉलर की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे डॉलर 20 साल के सबसे मजबूत स्थिति में पहुंच गया है. इसका सीधा असर रुपये पर भी दिख रहा।

आयातकों को घाटा, निर्यातकों को होगा लाभ

रुपये में गिरावट से आयातकों को नुकसान होगा, जबकि निर्यातकों को फायदा होगा। किसी वस्तु का आयात करने पर हमें डॉलर में ज्यादा रुपया देना होगा। निर्यात में डॉलर के हिसाब से कारोबारियों को ज्यादा रुपया मिलेगा।

आगे भी बना रहेगा दबाव

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के दिलीप परमार ने कहा कि दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने और डॉलर की उच्च मांग से अप्रैल-जून तिमाही में रुपये पर दबाव बढ़ा है। यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है और रुपया 79.10 के पार जा सकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि आरबीआई को रुपये की गिरावट को रोकने के तरीके को बदलने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि उसका अभी तक का तरीका रुपये की गिरावट को केवल तेज कर रहा है।

असम में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट साथ आए, देंगे दो करोड़ रुपये

नई दिल्ली। वॉलमार्ट फाउंडेशन और फ्लिपकार्ट फाउंडेशन ने गुरुवार को घोषणा की है कि वे दोनों मिलकर असम में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए दो करोड़ रुपये (2,50,000) रुपये का योगदान देंगे। संस्था की ओर से दिए गए फंड्स का इस्तेमाल कर डॉक्टर्स फॉर यू नाम की संस्था बाढ़ से प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करेगी। वॉलमार्ट फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सीईओ जूली गेहर्कि ने कहा है कि हमारी हमदर्दी उन लोगों के साथ है जो असम में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हम फ्लिपकॉर्ट फाउंडेशन की मदद से बाढ़ से प्रभावित होने वाली आबादी के लिए चलाए जा रहे राहत कार्य में अपना हर संभव योगदान देंगे।

वहीं फ्लिपकार्ट ग्रुप के चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर, रजनीश कुमार ने इस बारे में बताते हुए कहा है

कि असम के लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और हमारा प्रयास है कि हम लोगों को हर जरूरी सहायता देखभाल और करुणा उपलब्ध करवाएं। हम अपने संगठन के सहयोगियों की मदद से बाढ़ से प्रभावित इलाकों में हर जरूरी संसाधन मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि देश में असम और कई अन्य राज्यों में बाढ़ की सूचना के बाद फ्लिपकार्ट अपनी सीएसआर कार्यक्रम के तहत गूंज नाम की संस्था के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए फंड्स जुटाने का भी कार्य कर रही है।

इंग्लैंड ने दूसरा एकदिवसीय जीतकर सीरीज में बराबरी हासिल की

लंदन (एजेंसी)।

इंग्लैंड ने दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को 100 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल की है। इस मैच में मेजबान टीम इंग्लैंड की जीत में नये गेंदबाज रीस टॉपली की अहम भूमिका रही। बाएं हाथ के मध्यम तेज गति के गेंदबाज टॉपली ने 24 रन देकर 6 विकेट लिए। लॉर्ड्स स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने 49 ओवर में 246 रन बनाये। इसके बाद भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 38.5 ओवर में 146 रनों पर ही सिमट गयी। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर मेजबानों को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया।

इंग्लैंड टीम ने मोईन अली के 47 और डेविड विली के 41 रनों की सहायता से 246 रन बनाये। भारत की ओर से स्पिनर युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मेजबान गेंदबाज टॉपली ने सलामी बल्लेबाजों रोहित शर्मा को खाता खोले बिना ही पेवेलियन भेज दिया। , शिखर धवन भी 9 रन बनाकर आउट हो गये। इसके बाद सूर्यकुमार यादव 27 और अनुभवी विराट 16 रन बनाकर आउट हुए। टॉपली ने 9.5 ओवर में केवल 24 रन देकर 6 विकेट लिए। वहीं डेविड विली, ब्रायडन कार्स, लियाम लिविंगस्टोन और मोईन अली को 1-1 विकेट मिला।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी शून्य पर ही आउट हो गये। हार्दिक पंड्या को मोईन अली ने अपना शिकार बनाया। हार्दिक ने 29 रन बनाए। वहीं रवींद्र जडेजा भी 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे. मोहम्मद शमी ने 28 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का लगाते हुए 23 रन का योगदान दिया.

सिंगापुर ओपन : सिंधू ने हान को रोमांचक मुकाबले में हराया, सेमीफाइनल में पहुंची

सिंगापुर (एजेंसी)।

सिंगापुर ॰ दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधू ने चीन की हान यूइ को एक घंटे से अधिक चले मुकाबले में हराकर सिंगापुर ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी ने एक सेट गंवाने के बाद 17.21, 21.11, 21.19 से जीत दर्ज की। सिंधू का अब इस चीनी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ रिकॉर्ड 3.0 का हो गया है।

मई में थाईलैंड ओपन के बाद सिंधू पहली बार सेमीफानल में पहुंची है। अब देखना यह है कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से पहले वह खिताब जीत पाती हैं या नहीं। सिंधू का सामना अब गैर वरीय साइना कावाकामी से होगा। जापान की इस खिलाड़ी ने छठी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की पोर्नपावी चोचुवोंग को 21.17, 21.19 से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। साइना नेहवाल और एच एस प्रणय भी शाम को क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे।

दुनिया की 19वें नंबर की खिलाड़ी सिंधू को पहले गेम में काफी दिक्कतें आई। वह रक्षात्मक खेल में पिछड़ गई लेकिन दूसरे गेम में वापसी करके ब्रेक तक तीन अंक की बढत बना ली। ब्रेक के बाद क्रॉसकोर्ट पर विनर लगाकर लगातार सात अंकों के साथ बराबरी की। तीसरे गेम में मुकाबला काफी रोमांचक रहा लेकिन सिंधू ने संयम बनाकर खेलते हुए जीत दर्ज की।

पद पर बने रहने के लिए दादा और शाह की जोड़ी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

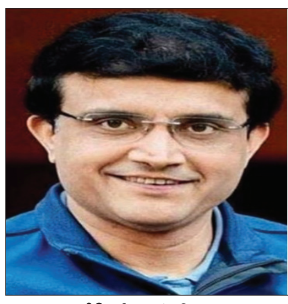

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड में है और वहां वनडे सीरीज़ खेल रही है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के अलावा बीसीसीआई से जुड़े बड़े अधिकारी और पूर्व क्रिकेटर भी इंग्लैंड में मैच देखते हुए दिखाई पड़े जिसमें अध्यक्ष सौरव गांगुली भी शामिल थे। इस सबसे इतर बीसीसीआई से जुड़ा एक अहम डेवलेपमेंट देश में हुआ है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को बोर्ड में कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन बीसीसीआई की ओर से अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। बोर्ड का कहना है कि दोनों के कार्यकाल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। बीसीसीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है कि नियमों में संशोधन को लेकर जो बोर्ड ने याचिका दायर की है, उसकी सुनवाई जल्द होनी चाहिए। इस इस अपील पर चीफ जस्टिस एनवी. रमणा द्वारा कहा गया है कि वह देखते हैं कि क्या इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बोर्ड की ओर से 2019 में ही एक याचिका सर्वोच्च अदालत में डाली गई थी, जिसमें बीसीसीआई के संविधान में संशोधन की अपील की गई थी। इस याचिका में बोर्ड की ओर से अध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों के कूलिंग ऑफ पीरियड को बढ़ाने की मांग की गई थी, साथ ही संविधान से जुड़े कुछ अन्य नियमों में बदलाव करने की इजाजत मांगी गई थी।

जल्द होने वाला है क्रिकेट के मैदान पर भारत-पाकिस्तान मुकाबला

कोलकाता (एजेंसी)।

कुआलालंपुर में 1998 के सत्र में पुरुषों के टूर्नामेंट के आयोजन के बाद पहली बार महिला क्रिकेट को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है।बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 28 जुलाई से आठ अगस्त तक होगा। क्रिकेट मैच का सेमीफाइनल छह अगस्त और फाइनल सात अगस्त को खेला जायेगा। भारत ग्रुप ए में है और वह 29 जुलाई को अपने शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। पाकिस्तान और बारबाडोस ग्रुप की अन्य दो टीमें हैं।गौरतलब है कि पाकिस्तान आज तक भारत से वनडे मैच नहीं जीत सका है। हाल ही में हुए महिला विश्वकप में भारत को टक्कर तो मिली थी लेकिन पाक के बल्लेबाज जरूरी लक्ष्य 240 के आस पास भी नहीं फटक पाए थे। अब एक बार फिर यह दोनों टीमें भिड़ने वाली

है, तो दर्शकों का रोमांच चरम पर होने की उम्मीद है। भारतीय टीम से इस बार मिताली राज और झूलन गोस्वामी नहीं नजर आएंगी लेकिन इसके बावजूद भारत कागज पर अपने एशियाई चिरप्रतिद्वंदी से खासा मजबूत है।

पुरुष क्रिकेट में भी जल्द होगी भिड़ंत

एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक प्रस्तावित है। इससे पहले 20 अगस्त से 26 अगस्त तक क्वालीफ़ायर मुक़ाबले खेले जाएंगे, जिसमें हॉन्ग-कॉन्ग, कुवैत, सिंगापोर और यूएई जैसे देश हिस्सा लेंगे। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने इस टी20 टूर्नामेंट के लिए सीधा क्वालीफ़ाई किया है। इस टूर्नामेंट में भी भारत पाकिस्तान की भिडंत होगी ही।

इस साल कुल 4 बार हो जाएगा आमना सामना

कोरोना और राजनीतिक संबंधो के कारण यह दोनों देश पिछले कुछ सालों में उतनी क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। फिर चाहे महिला टीम हो या फिर पुरुष टीम। लेकिन इस बार 2 बार महिला टीम और 2 बार पुरुष टीम का मैच दर्शकों को देखने को मिल सकता है।

महिला टीम वनडे विश्वकप में एक बार आमने सामने हो ही गई है। अब राष्ट्रमंडल खेल में भी यह दोनों टीमें आमने सामने होंगी।

मार्टिन गुप्टिल ने शतक लगाकर हासिल की बढ़ी उपलब्धियां, धवन की बराबरी भी की

खेल डैस्क (एजेंसी)।

न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गुप्टिल ने आयरलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे में शानदार शतक लगाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। फिन ऐलन के साथ ओपनिंग पर आए गुप्टिल ने विकेट के चारों ओर शॉट लगाए और 126 गेंदों में 15 चौके और 2 छक्कों की मदद से 115 रन बनाए। वह 38वें ओवर में आऊट हुए। अगर वह आखिर तक नाबाद रहते तो उनके बल्ले से दोहरा शतक भी देखा जा सकता था। बता दें कि मार्टिन गुप्टिल वनडे की एक पारी में नाबाद 237 रन बना चुके हैं।

बहरहाल, मार्टिन ने अपने वनडे करियर का 17वां शतक लगाया। ऐसा कर उन्होंने भारतीय ओपनर शिखर धवन, क्विटंम डिकॉक, एरोन फिंच, जैक कैलिस की बराबरी की। यही नहीं उनके वनडे फार्मेट में सात हजार रन भी पूरे हो गए हैं।

17 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचेगा ईसीबी का जांच दल

लंदन। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कहा है कि टीम के पाकिस्तान दौरे से पहले सुरक्षा हालातों का जायजा लेने के लिए एक जांच दल पाक भेजा जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को सितंबर में 7 टी20 मैचों के लिए पाकिस्तान दौरे पर जाना है। इस सीरीज के जरिये उसे अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 विश्वकप के लिए अभ्यास का अच्छा अवसर मिलेगा पर ईसीबी उससे पहले टीम की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त होना चाहता है। इसी को देखते हुए ईसीबी का चार सदस्यीय सुरक्षा जांच दल 17 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचेगा। इंग्लैंड टीम ने पिछले साल सुरक्षा मामले को लेकर ही पाक दौरा रद्द कर दिया था। ऐसे में वह इस बार किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता है। ईसीबी के इस 4 सदस्यीय जांच दल के 17 जुलाई को आने की संभावना है। इस दल में प्लेयर्स एसोसिएशन, सिक्यूरिटी और क्रिकेट ऑपरेंशस के सदस्य शामिल हैं। वे कराची, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद जाएंगे। इसी रिपोर्ट के आधार पर ही इंग्लैंड टीम के दौरे की योजना बनायी जाएगी। जानकारी के अनुसार टी20 के मुकाबले केवल दो स्थलों पर ही खेले जाएंगे।

मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सऊदी अरब के क्लब से मिला बंपर ऑफर

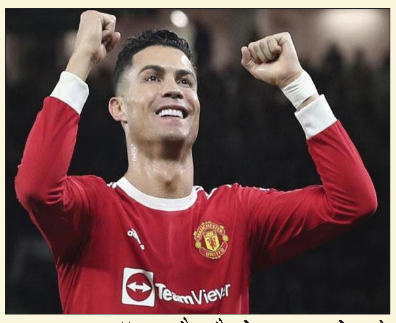

मशहूर फुटबॉलर और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुख्य खिलाड़ियों में शामिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सऊदी अरब के एक क्लब द्वारा 200 मिलियन पाउंड से अधिक का ऑफर मिला है। 37 वर्षीय रोनाल्डो का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अगली गर्मियों तक अनुबंध है, लेकिन उन्होंने क्लब को सूचित किया कि वह नए सत्र से पहले क्लब छोड़ना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो को एक बेनामी सऊदी अरब क्लब से दो वर्षों के लिए 233.23 मिलियन पाउंड का आकर्षक ऑफर मिला है। सऊदी अरब का यह क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को 25 मिलियन पाउंड का स्थानांतरण शुल्क का भुगतान करने को भी तैयार है। हालांकि रोनाल्डो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि अगले सत्र में चैंपियंस लीग में खेलने की उनकी महत्वाकांक्षा बनी हुई है। चेल्सी ने इन गर्मियों में रोनाल्डो को साइन करने का कोई प्रयास नहीं करने का फैसला किया है, हालांकि एटलेटिको मैड्रिड सहित अन्य क्लब अभी भी रुचि बनाए हुए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बार-बार जोर देकर कहा है कि रोनाल्डो बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन खिलाड़ी व्यक्तिगत कारणों के कारण क्लब के थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्री-सीजन दौरे पर नहीं गया था।

स्पेन के खिलाफ हार से निराश लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रदर्शन में करेंगे सुधार: नवनीत

बारबाडोस (एजेंसी)।

टेरासा ॰ भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉर्वर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर ने गुरुवार को कहा कि एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में नौंवे स्थान पर रहने के बाद भारत राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अपना प्रदर्शन सुधारना चाहेगी। जापान के खिलाफ विश्व कप मैच में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाली नवनीत ने कहा कि मैं खुश हूं कि मैं टीम की जीत में योगदान दे पाई। विश्व कप में खेले गए मैचों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम राष्ट्रमंडल खेलों में अपना प्रदर्शन सुधारने पर काम करेंगे।

भारत शीर्ष 8 से चूका

स्पेन के हाथों क्रॉसओवर मैच में 0-1 से हारने के बाद भारत ने शीर्ष आठ में जगह पाने का अवसर गंवा दिया था। नवनीत ने इस हार के बारे में कहा कि

जब हम स्पेन के खिलाफ मैच हारे तो हम बेहद निराश थे लेकिन हमें पता था कि हमें जल्द ही उस मैच को पीछे छोड़कर कनाडा और जापान के खिलाफ होने वाले मैचों पर ध्यान देना है।

कनाडा पर जीत दर्ज करना चाहेंगे

नवनीत ने कहा कि हम सिर्फ इन दोनों टीमों के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना विश्व कप अभियान को सकारात्मकता के साथ समाप्त करना चाहते थे। भारत ने अपने 9वें-16वें स्थान के मैच में नियमन समय के अंत तक 1-1 से बराबरी करने के बाद शूटआउट में कनाडा को 2-3 से हराया। इसके बाद भारत का मुकाबला 9वें-12वें स्थान के मैच में जापान से हुआ जहां उन्होंने 3-1 से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में नौंवा स्थान हासिल किया।

हमने कई मौके गंवाए

नवनीत ने कहा कि मुझे लगता है कि हम कनाडा के खिलाफ और भी बेहतर कर सकते थे और मैच को शूटआउट में नहीं जाने से रोक सकते थे। हमने सर्कल में कई मौके गंवाए। जापान के खिलाफ, यह महत्वपूर्ण था कि हम अपने अवसरों में सुधार करें और हमने पहले मिनट से ही ऐसा किया। महिला टीम बर्मिंघम में 28 जुलाई से शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अपना पहला मैच 29 जुलाई को घाना के खिलाफ खेलेगी।

अपनी उपेक्षा से निराश है साइना : कश्यप

नई दिल्ली । अनुभवी महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल के पति और शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप ने कहा है कि साइना अपनी उपेक्षा से निराश थी। कश्यप ने कहा कि इसी कारण सिंगापुर ओपन के पहले दौर में मालविका बंसोड़ के खिलाफ मैच से पहले जबरदस्त दबाव में थीं हालांकि साइना ने यह मुकाबला आसानी से जीत लिया था। इससे पहले साइना को इंडिया ओपन में मालविका के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कश्यप के अनुसार बैडमिंडन फेडरेशन ने साइना की इसी हार को आधार बनाकर उन्हें राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए टीम में जगह नहीं दी थी। वहीं अब साइना ने सिंगापुर ओपन में चीन की बिंगजियाओ के खिलाफ शानदार जीत दर्ज कर अपने को साबित किया है। कश्यप के अनुसार राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए चयन ट्रायल ऐसे समय रखे गए थे। जब साइना चोट से उबर ही रहीं थी और इसी कारण उबर कप के दौरान उनका फेडरेशन से चयन को लेकर विवाद भी हुआ था। इसके बाद इसी को आधार बनाकर बैडमिंटन संघ ने राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए साइना को शामिल नहीं किया। इससे वह बेहद निराश हुईं थी और अक्सर रोने लगती थीं। इसके बाद से ही उसके लिए अभ्यास तक करना कठिन हो गया था। कश्यप के अनुसार साइना बैडमिंटन संघ ने साइना के मैसेज तक का जवाब नहीं दिया था जिससे वह दुखी थीं। वहीं बैडमिंटन संघ का कहना है कि उन्होंने साइना से अपने फिटनेस स्टेटस की जानकारी देने को कहा था जो नहीं मिली थी। इसी कारण उन्हें जगह नहीं दी गयी।

आईएसएसएफ विश्व कप में भारत की पुरूष निशानेबाजी टीम को मिला स्वर्ण

चांगवोन। भारतीय पुरूष निशानेबाजी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में एक स्वर्ण और तीन रजत पदक जीते हैं। भारत के अर्जुन बबुता, शाहू तुषार माने और पार्थ मखीजा की टीम ने फाइनल में मेजबान कोरियाई टीम को 17-15 से हराकर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। वहीं रमिता, एलावेनिल वलारिवन और मेहुली घोष की एयर राइफल महिला टीम को कोरिया के हाथों 10-16 से हार के कारण रजत पदक ही मिला। इससे पहले पुरूष और महिला राइफल टीम ने 629.7 और 631.5 अंकों के साथ ही शीर्ष स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक मैच के लिए क्वालीफाई किया था। भारत के ही शिव नरवाल नवीन और सागर डांगी की जोड़ी को एयर पिस्टल पुरूष टीम स्पर्धा में इटली के हाथों 15-17 से हारने के कारण रजत पदक मिला। रिदम सांगवान, पलक और युविका तोमर की एयर पिस्टल टीम को भी फाइनल में कोरिया के खिलाफ 12-16 से हार के साथ ही रजत पदक ही मिल पाया। ।

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम डोपिंग जांच में विफल होने पर 10 महीने के लिये प्रतिबंधित

दुबई (एजेंसी)।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को मार्च में टूर्नामेंट से इतर हुए डोप परीक्षण में विफल पाये जाने के बाद गुरूवार को 10 महीने के लिये प्रतिबंधित कर दिया। शोहिदुल के मूत्र के नमूने में क्लोमीफेन पाया गया जिसे वाडा की प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत निर्दिष्ट पदार्थों की सूची में रखा गया है। यह टूर्नामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रतिबंधित है। आईसीसी के टूर्नामेंट से बाहर जांच के कार्यक्रम के अंतर्गत उनके मूत्र का नमूना लिया गया था। आईसीसी ने एक बयान में कहा, ''बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को आईसीसी डोपिंग रोधी संहिता के अनुच्छेद 2.1 के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद 10 महीने के लिये प्रतिबंधित किया जाता है।' इसमें कहा गया, 'उल्लंघन स्वीकार करने के बाद शोहिदुल को 10 महीने के लिये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया जाता है। ' निलंबित करते हुए आईसीसी ने हालांकि पुष्टि की कि शोहिदुल ने दवाई के रूप में प्रतिबंधित पदार्थ का अनजाने में सेवन किया जो उन्हें उपचार के उद्देश्य से दी गयी थी। यह 10 महीने का प्रतिबंध 28 मई से शुरू होगा जिससे बांग्लादेश का यह तेज गेंदबाज 28 मार्च 2023 तक क्रिकेट नहीं खेल पायेगा। इस 27 साल के खिलाड़ी ने बांग्लादेश के लिये अभी एक ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है जिसमें उन्होंने श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मैच में मोहम्मद रिजवान का विकेट लिया था और इसमें पाकिस्तान 3-0 से जीता था।

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रीस टॉपली ने चटके 6 विकेट, कहा- क्रिकेट से ब्रेक का लाभ मिला

लंदन। (एजेंसी)।

भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में छह विकेट लेकर इंग्लैंड को सौ रन से जीत दिलाने वाले बायें हाथ के तेज गेंदबाज रीस टॉपली ने कहा कि हाल ही में चोटों के कारण क्रिकेट से दूर रहने का उन्हें फायदा मिला। पहले मैच में दस विकेट से हारने के बाद शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को सौ रन से हराया। टॉपली ने 24 रन देकर छह विकेट लिये। उन्होंने पूर्व कप्तान पॉल कोलिंगवुड का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 31 रन देकर छह विकेट लिये थे। अब दोनों टीमें रविवार को तीसरा और आखिरी वनडे खेलेंगी।

टॉपली ने कहा ,'' यह शानदार टीम प्रदर्शन था। यह काफी मायने रखता है। हर किसी का सपना इंग्लैंड के लिये खेलने का होता है। अब रविवार को बड़ा मैच है जिसे जीतकर हम श्रृंखला अपने नाम करने की कोशिश करेंगे।'' सात साल पहले इंग्लैंड के लिये पहला मैच खेलने वाले टॉपली 17 वनडे खेल चुके हैं।चोटों के कारण उनका कैरियर बुरी तरह प्रभावित हुआ लेकिन वह वापसी को भुनाने के लिये बेताब हैं।

उन्होंने कहा ,'' मैं जितनी बार हो सके, इंग्लैंड के लिये खेलना चाहता हूं और जीत में योगदान देना चाहता हूं। यह सौभाग्य की बात है।'' इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने स्वीकार किया कि उनकी टीम एक बार फिर बल्लेबाजी में नाकाम रही लेकिन टॉपली के जुझारूपन की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा ,'' उसकी कहानी दिलचस्प है। वापसी करके लाडर्स पर छह विकेट लेना शानदार है। उसका अनुभव कठिन था और उसे पता भी नहीं था कि वह दोबारा खेल भी सकेगा या नहीं और उसके बाद इस तरह का प्रदर्शन वाकई काबिले तारीफ है।

पेनल्टी कार्नर के कई विशेषज्ञों से लाभ मिलेगा : संदीप सिंह

नई दिल्ली । भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने कहा कि टीम में पेनल्टी कार्नर के कई अच्छे विशेषज्ञों के शामिल होने से आगामी टूर्नामेंटों में भारतीय टीम को लाभ होगा। भारतीय टीम को अभी बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेना है। जिसमें हरमनप्रीत सिंह, वरूण कुमार और अमित रोहिदास जैसे ड्रैग फ्लिकर अहम भूमिका निभा सकते हैं , ऐसे में टीम के पास स्वर्ण जीतने का अवसर है। वहीं संजय, अरिजीत सिंह हुंदल और सुदीप चिरमाको जैसे जूनियर खिलाड़ी भी काफी अच्छे ड्रैग फ्लिकर हैं जो अभिष्य में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। संदीप ने कहा कि ड्रैग फ्लिकर बनना आसान नहीं है। इसमें पारंगत होने में काफी समय लगता है। यह काफी तकनीकी चीज है, जहां आपको शारीरिक ताकत के साथ ही हाथों को भी तेजी से चलाना होता है। उन्होंने कहा कि अधिक ड्रैग फ्लिकर होने से टीम को विविधता का लाभ मिलता है।

परिचय

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। खाद्य के मूल्यों में अत्यधिक उतार - चढ़ाव, मौसमी और कम समय के लिए मूल्य वृद्धि और अनियमित मानसून को देखते हुए कृषि क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों के लिए एह एक कठिन चुनौती है। इसके बावजूद किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को अवश्य हासिल किया जा सकता है। खेत उत्पादकता में सुधार लाने, खेती की लागत को कम करने, अखिल भारतीय स्तर पर बाजार पहुँच को सुनिश्चित करने आदि की दिशा में सामूहिक प्रयास से इस लक्ष्य की प्राप्ति में काफी आसानी हो सकती है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। की इस लक्ष्य को हासिल करने में कंदीय फसलों की मुख्य भूमिका होगी।

कंदीय फसलों से भरपूर आमदनी

बागवानी से भरपूर आय

बागवानी क्षेत्रों में किसानों की आय को बढ़ाने की भरपूर क्षमता है। इसलिए पारंपरिक अनाजीय फसलों से उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की ओर बदलाव करने से से भारत में किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में व्यापक पैमाने पर योगदान किया जा सकेगा। बागवानी फसलों में भी विशेषत- कंदीय फसलें इस लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनमें अभूतपूर्व उच्च प्रति इकाई उत्पादकता पाई जाती है। हालाँकि एक सम्यक रीति में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्पादन क्लस्टरों को इनपुट के साथ - साथ उपभोक्ता बाजारों से अच्छी तरह से जोड़ने की जरूरत है यह संदेह से परे है कि कृषि इनपुट और उत्पादन से जुड़े सूक्ष्म - लघु - छोटे तथा माध्यम स्तरीय उद्यमों की स्थापना से ग्रामीण भारत की आजीविका सुरक्षा में प्रभावी तरीके से सुधार किया जा सकता है। कंदीय फसलें ग्राम स्तर पर ही ऐसे उद्यमों को स्थापित करने के भरपूर अवसर प्रदान करती हैं। कंदीय फसल अनुसंधान पर कहीं अधिक ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें शामिल है- गैर- पारंपरिक क्षेत्रों में इनकी खेती का विस्तार करना, कंदीय फसलों की पोषणिक एवं खाद्य सुरक्षा भूमिका का पूर्वानुमान करना, मूल्यवर्धित खाद्य, आहार एवं औद्योगिक उत्पादों का विकास करके उपयोगिता संभावनाओं को बढ़ाना, अमंग आकलन रण नीतियाँ विकसित करना, नये बाजार विकल्पों की तलाश करना, औषधीय प्रभावों वाले हर्बल उत्पादों, जैव कीटनाशकों, प्राकृतिक खाद्य रंगों का विकास करना जैसे अल्प दोहित क्षेत्रों की खोज करना आदि। प्रौद्योगिकीय प्रगति का प्रभावी तरीके सेड प्रदर्शन और प्रसार करने. उत्पादकता में और सुधार करने और ग्रामीण जनसंख्या तक लाभ पहुँचाने के लिए इन फसलों की उपयोगिता संभावनाओं का खुलासा करने में काफी मदद मिल सकती है।

कंदीय फसलों में मूल्यवर्धन

उष्णकटिबंधीय कंदीय फसलों में न केवल खाद्य फसलों के रूप में महत्ता हासिल की है वरन इनकी आहार और कृषि आधारित उद्योगों में भी व्यापक संभावनाएं हैं। खाने - पीने की आदतों में तेजी से हो रह बदलाव और प्रति व्यक्ति आमदनी में अनुमानित बढ़ोतरी के साथ शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ते देशांतर से अगले 30 - 40 वर्षों में प्रसंस्करित और रेडी टू ईट (खाने के लिए तुरंत तैयार) सुविधाजनक खाद्य में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। उस परिदृश्य में कंदीय फसलों से रोग - निरोधी और चिकित्सीय कार्यशील खाद्य विकसित करने की व्यापक संभावना विद्यमान है।

आलू, कसावा, शकरकंद, जिमीकंद, कचालू, टेनिया, याम (रतालू), याम बीन, अरारोट आदि जैसी कंदीय फसलें स्टार्चयुक्त भंडारण अवयव के रूप में संशोधित जड़ अथवा तने के साथ पौधों का एक समूह बनाती हैं। इनमें कहीं अधिक जड़ें, घनकंद, राइजोम्स होते है और इनके कंदों की खुदाई आमतौर पर जमीन से नीचे की जाती है। ये फसलें अनाज एवं दाना फसली के उपरांत तीसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसलें हैं और प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उच्च शुष्क सामग्री उत्पादन के साथ खाद्य उत्पादक रूप में अपनी जैविक प्रभावशीलता के आधार पर ये फसलें अनूठी हैं। ऊर्जा उत्पादन में आलू सबसे आगे (216 मेगाजूल/हे./दिन) एवं इसके बाद क्रमशः रतालू (181 मेगाजूल/हे./दिन), शकरकंद (152 मेगाजूल/हे./दिन), तथा कसावा (121 मेगाजूल/हे./दिन) का स्थान है। कंदीय फसलें विश्व की 1/5 आबादी के लिए मुख्य अथवा सहायक खाद्य के तौर पर उष्णकटिबंधीय तथा अर्द्ध उष्णकटिबंधीय देशों में लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

उपयोगी प्रौद्योगिकियां

ऐसे किसान जो आलू और अन्य कंदीय फसलों की खेती करते हैं, वे उपयुक्त फसल किस्म, आधुनिक उत्पादन एवं संरक्षण तकनीकें अथवा बचाव प्रौद्योगिकियों को अपनाकर अपनी फार्म आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। भाकृअनुप - केंद्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम जैसे शोध संस्थानों द्वारा आलू और अन्य कंदीय फसलों की अधिक पैदवार देने वाली अनेक किस्में और प्रौद्योगिकियां विकसित की गई है। कुछ प्रौद्योगिकियां राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा भी विकसित की गई हैं और वे किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इन प्रौद्योगिकियों की पहुँच अभी बहुत सीमित हैं। इन्हें किसान समुदाय के बीच लोकप्रिय बनाये जाने की जरूरत है ताकि कंदीय फसलों में वर्तमान पैदावार अंतराल को कम किया जा सके। आलू और अन्य कंदीय फसलों की उत्पदकता को बढ़ाने के लिए यहाँ प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेपों पर जानकारी देने का प्रयास किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री

अधिकांश कंदीय फसलों को तने के टूकड़ों अथवा कंद का उपयोग करके शाकीय रूप से प्रवर्धित किया जाता है। इसलिए बीज की गुणवत्ता को बनाये रखना विशेषकर इसे वायरस तथा अन्य रोगजनकों से मुक्त रखना बहुत आवश्यक होता है। भारत में आलू उत्पादकों के समक्ष गुणवत्ता आलू बीज की उपलब्धता अभी भी एक प्रमुख समस्या है। इसीलिए यह जरूरी है कि किसानों को सस्ते दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति की जाये। किसान स्वयं भी भाकृअनुप - केंद्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा विकसित की गई बीज प्लाट तकनीक का उपयोग आलू बीज उगा सकते हैं। यह प्रौद्योगिकी पिछले 50 वर्षों से भारत में आलू के उत्पादन और उत्पादकता क्षेत्र में उल्लेखनीय बढ़ोतरी में मुख्य भोमिका निभा रही है। वायरस की पहचान करने वाली उन्नत तकनीकों, पौध बचाव उपायों और सस्यविज्ञान रीतियों के साथ बीज प्लाट तकनीक का एकीकरण करने से भारत में प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम की मजबूत बुनियाद रखने को बढ़ावा मिला है। हाल ही में हाइटेक बीज उत्पादन प्रौद्योगिकियां जैसे कि ऊतक संवर्धन से तैयार लघु कंद के साथ - साथ ऐरोपॉनिक प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार लघु कंद का विकास किया गया हैझ इन्हें गुणवत्तायुक्त आलू बीज के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐरोपॉनिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, आलू पौधों को एक बंद अथवा संरक्षित वातावरण में उगाया जाता है और मृदा अथवा किसी अन्य समुच्य मीडियम का उपयोग किये बिना पोषण से भरपूर घोल का साथ समय - समय पर जड़ों पर छिड़काव किया जाता है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का तेजी से गुणन होता है, जिसमें प्रति ऊतक संवर्धन पादप 35 - 60 लघुकंद उत्पन्न होते हैं। इसमें अनेक मृदा जनित रोगजनकों के आलू कंदों के साथ सम्पर्क में कमी आती है। इसके अलावा इसे ऑपरेट करना भी आसान होता है। इस प्रणाली को गौरवायविय तथा पानी की कमी वाले इलाकों में स्थापित किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी अत्यधिक लागत प्रभावी है, जिसमें 10 लाख कंदों के उत्पादन के लिए 100 लाख रूपये का निवेश करने की जरूरत होती है और कोई भी उद्यमी इससे प्रति वर्ष 52 लाख रूपये तक कमा सकता है। अत- ऊतक संवर्धन और ऐरोपॉनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत में पारंपरिक बीज उत्पादन प्रणाली में क्रन्तिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। भाकृअनुप - केंद्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम द्वारा मानकीकृत मिनी सेट प्रौद्योगिकी को अपना कर उष्णकटिबंधीय कंदीय फसलों में भी वायरसमुक्त गुणवत्ता रोपण सामग्री को विकसित किया जा सकता है।

अनाज फसलों की तुलना में कंदीय फसलों से अधिक लाभ

चावल, गेंहू और मक्का जैसे पारंपरिक अनाज फसलों की तुलना में फल व सब्जियों जैसे बागवानी फसलें कहीं अधिक लाभ प्रदान करती हैं। उच्च मूल्य वाली फसलों और उद्यमों की दिशा में कृषि गतिविधियों का विविधीकरण करना किसानों की आय को बढ़ाने में एक प्रमुख चालक बन सकता है। भारत के तीन मुख्य राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए चावल व गेहूं जैसे अनाज फसलों और प्रमुख कंदीय फसल आलू में खेत की लागत और शुद्ध आय के तुलनात्मक अध्ययन को सरणी - 1 में दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि सभी चयनित राज्यों के लिए आलू की खेती की लागत चावल और गेहूं से कहीं ज्यादा है, जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रूपये 1,08,860,30 प्रति हे. है। उत्तर प्रदेश में आलू से मिलने वाली प्रति हे. शुद्ध आय चावल और के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में आलू से मिलने वाली प्रति हे. शुद्ध आय रूपये 36,519,70 है, जो कि चावल तथा गेहूं की तुलना में लगभग तीन गुना है। बिहार में गेहूं (प्रति हे. रूपये 26,835,70) के मुकाबले आलू (प्रति हे. रूपये 32,787,00) में कहीं अधिक लाभ मिला। बिहार में किसानों के लिए धान की खेती आलू की ही तरह लाभप्रद नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें प्रति हे. केवल रूपये 6,277,70 का कम लाभ ही मिल रहा है। अत- यह देखा जा सकता है कि पारंपरिक अनाज फसलों के मुकाबले आलू जैसी कंदीय फसल की खेती करके किसान कहीं अधिक लाभ कमा सकते हैं।

उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियां

भारत में कृषि केवल लाभ अर्जित करने वाला व्यवसाय नहीं है बल्कि यह 138 मिलियन से भी अधिक कृषिजोत पर काम करने वाले परिवारों के लिए परंपरा का हिस्सा है इनमें से 85 प्रतिशत परिवारों के पास 2 हे. से भी कम आकार वाली कृषिजोत हैं। इनमें से अधिकांश कृषिजोत का उपयोग बहु कृषि गतिविधियों यथा कृषि/बागवानी, पोल्ट्री एवं पशु पालन, मत्स्यिकी, मधुमक्खी पालन रेशमा पालन तथा वानिकी में किया जाता है। इन छोटी तथा सीमांत कृषिजोत में फसलचक्र सघनता बहुत अधिक होती है। यहाँ तक कि प्राय- यह 300 प्रतिशत तक भी पहुँच जाती है।

फायदे का सौदा आलू

भारतीय समाज में आलू सर्वाधिक प्रचलित सब्जी है। देश में सब्जियों के तहत कूल कृषि में यह 21 प्रतिशत क्षेत्र में बोई जाती है और कुल सब्जी उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 25.50 प्रतिशत है। चीन के बाद भारत आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब राज्यों को शामिल करते हुए भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में देश के कुल आलू उत्पादन का 85 प्रतिशत से भी अधिक उत्पादन होता है। वर्ष 2014 - 15 में भारत में 23.1 टन/हे. की औसत उत्पादन हुआ। लगातर बढ़ रही जनसंख्या के साथ भविष्य में भारत में आलू की खपत कई गुना बढ़ने का अनुमान है।

जल बचत

आलू सहित किसी भी फसल की खेती के लिए सिंचाई जल इ=की म=कमी प्रमुख समस्या है। आधुनिक आलू किस्में जल की कमी वाली मृदाओं के प्रति संवेदनशील होती है और उनमें बार - बार उथली सिंचाई करने की जरूरत होती है। आमतौर पर पानी की कमी फसल की बढ़वार अवधि के मध्य से पिछेती भाग में भूस्तारी अथव स्टोलन गठन और कंद की शुरूआत तथा बल्किंग के दौरान होती है। इससे पैदावार में कमी होने की आशंका रहती है। अगेती फसलें शाकीय वृद्धि के दौरान कम संवेदनशील होती हैं। फसल पकने वाले अवधि की ओर उच्चतर रिक्तिकरण को अपनाकर भी जल की बचत की जा सकती है ताकि फसल द्वारा अपने जड़ क्षेत्र में भंडारित उपलब्ध पूरे जल का उपयोग किया जा सके। इस क्रियाविधि अथवा रीति से परिपक्वता को भी जल्दी किया जा सकता है और शुष्क पदार्थ सामग्री को बढ़ाया जा सकता है। कुछ किस्में कंद बल्किंग के अगेती भाग में सिंचाई के प्रति कहीं बेहतर प्रतिक्रिया देती हैं, जबकि अन्य बाद वाले हिस्से में कहीं बेहतर प्रतिक्रिया को दर्शाती हैं। कम कंदों वाली किस्में आमतौर पर अनके कंदों वाली किस्में आमतौर पर अनेक कंदों वाली किस्मों की तुलना में जल की कमी के प्रति कम संवेदनशील होती हैं। सिंचाई के लिए सही समय का चयन करके और पौधा वृद्धि चक्र की विशिष्ट अवस्था में जल प्रयोग की उपयुक्त गहराई का प्रयोग करके आलू की फसल में जल की जरूरत को किफायती बनाया जा सकता है। अब जलमग्न अथवा बाढ़ जैसे सिंचाई की तुलना में ड्रिप एवं स्प्रिकलर विधियों के माध्यम से सटीक रूप से सिंचाई करने के लिए प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं, जो न केवल पानी की बचत करती हैं वरन साथ ही उत्पादकता को भी बढाती हैं।

उन्नत फसलोत्तर प्रबंधन

खुदाई अथवा तुड़ाई करने के उपरांत, छिलकों के उपचार हेतु कंदों को 10 - 15 दिनों तक ढेर में रखा जाना चाहिए। यह जरूरी है की सभी क्षतिग्रस्त और सड़े हुए कंदों को हटा दिया अच्छा लाभ कमाने के लिए उत्पाद अर्थात कंदों की छटाई की जाये और उन्हें ग्रेडिंग के अनुसार जूट के थैलों में पैक किया जाए। किसान अधिक लाभ कम सकते है यदि अपने आलू को शीत भंडार में भंडारित किया जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए भंडारित किये गये आलू स्वाद में मीठे नहीं होंगे और इस प्रकार इनसे कहीं अधिक मूला हासिल किये जा सकता है। यह ध्यान दिया जाये कि बीज आलू को केवल 0 - 20 सेल्सियस तापमान पर ही भंडारित किया जाये। चिप्स, फ्रेंच फ्रेंचाइज, लच्छा आदि जैसे निर्जलीकृत आलू उत्पादों को तैयार करके आलू में मूल्यवर्धन करने से भी किसानों को आकर्षक लाभ मिल सकता है। भाकृअनुप - केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला में घरेलू स्तर पर मूल्य वर्धन करने की प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पाकिस्तान का पोलिया मुक्त अभियान पटरी से उतारा, उत्तर वजीरिस्तान में 12 नए मामले सामने आए

इस्लामाबाद । पाकिस्तान सरकार की अपने मुल्क को पोलियो मुक्त बनाने के प्रयासों के बीच आदिवासी क्षेत्र कहे जाने वाले उत्तर वजीरिस्तान में पोलियों के 12 नए मामले सामने आए है। पोलियो को लेकर जहां दुनिया भर में एक युद्ध स्तर पर काम करके पोलियो को हराया गया है, वहीं पाकिस्तान के साथ उसका पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान अभी भी पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे है। पाकिस्तान का नया मामला मीर अली इलाके से सामने आया है, जहां एक 21 महीने के बच्चे का एक पांव पोलियो की वजह से लक्वाग्रसित हो गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार बच्चे के दाहिने पैर में लकवा मार गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सभी 12 मामले खैबर पख्तूनख्वा के उत्तर वजीरिस्तान से सामने आए है। वहीं, खैबर पख्तूनख्वा के विशेष सूचना सहायक मुहम्मद अली सैफ ने कहा है कि प्रांतीय सरकार इस गंभीर बीमारी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के आम लोगों में धारणा बनी हुई है कि पोलियो की ड्रॉप पिलाने से आगे जाकर उनके बच्चों की प्रजनन क्षमता पर असर होगा है। इस कारण अधिकतर लोग अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने से बचते हैं। पाकिस्तान के गांव देहात में अक्सर लोगों द्वारा पोलियो मेडिकल टीम पर हमले की खबरें मीडिया में आम बात है।

कोविड के कारण दो करोड़ 50 लाख बच्चों का नहीं हो पाया नियमित टीकाकरण

जिनेवा। कोरोना वायरस महामारी के कारण नियमित स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होने या टीकाकरण को लेकर गलत सूचनाओं के प्रसार के कारण दुनिया भर में करीब दो करोड़ 50 लाख बच्चों का डिफ्थीरिया, टेटनस और काली खांसी जैसे रोगों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण नहीं हो पाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष (यूनिसेफ) द्वारा शुक्रवार को प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल करीब दो करोड़ 50 लाख बच्चों का डिफ्थीरिया, टेटनस और काली खांसी जैसे रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण नहीं हुआ। बच्चों के टीकाकरण में 2019 के बाद से गिरावट देखी जा रही है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा, ''यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 'रेड अलर्ट' है।'' उन्होंने कहा, ''हम एक पीढ़ी में बच्चों के टीकाकरण में सबसे बड़ी सतत गिरावट देख रहे हैं।'' आंकड़ों के अनुसार, जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, उनमें बड़ी संख्या में बच्चे इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और फिलीपीन जैसे विकासशील देशों में रहते हैं। हालांकि विश्व के हर क्षेत्र में टीकाकरण के मामले में गिरावट देखी गई है, लेकिन इसके सर्वाधिक मामले पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पाए गए हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि टीकाकरण की संख्या में ''ऐतिहासिक गिरावट'' इसलिए और भी अधिक परेशानी की बात है, क्योंकि यह ऐसे समय में देखी जा रही है, जब गंभीर कुपोषण के मामले बढ़ रहे हैं। कुपोषित बच्चों की रोग प्रतिरोधी प्रणाली आम तौर पर कमजोर होती है और खसरा जैसी बीमारी उनके लिए घातक हो सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि टीकाकरण की दर में कमी के कारण खसरा और पोलियो जैसी रोकी जा सकने वाली बीमारियों का संक्रमण देखा गया। डब्ल्यूएचओ और उसके साझेदारों ने मार्च 2020 में कोविड-19 के कारण देशों से अपने पोलियो उन्मूलन प्रयास निलंबित करने को कहा था। इसके बाद से 30 से अधिक देशों में पोलियो के मामलों में बढ़ोतरी पाई गई है।

शराब के सेवन से युवाओं में बढ़ जाता है स्वास्थ्य का जोखिम, लांसेट का अध्ययन

वाशिंगटन। युवाओं को ज्यादा उम्र वालों की तुलना में शराब के सेवन से अधिक स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है। शोध पत्रिका 'लांसेट' में शुक्रवार को प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन में यह बात कही गई है। भौगोलिक क्षेत्र, आयु, लिंग और वर्ष के आधार पर शराब से जुड़े जोखिम के बारे में यह पहला अध्ययन है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में शराब की खपत की सिफारिशें उम्र और स्थान पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें सबसे सख्त दिशानिर्देश 15-39 साल के आयु वर्ग के पुरुषों के लिए लक्षित हों। अध्ययन में कहा गया है कि इस उम्र समूह में शराब के सेवन से स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ जाता है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि अगर कोई गंभीर बीमारी ना हो तो 40 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों को कम मात्रा में शराब के सेवन से कुछ लाभ मिल सकते हैं। ऐसे में इस समूह को हृदय रोग, हृदयाघात और मधुमेह का जोखिम कम होता है। शोधकर्ताओं ने 204 देशों में शराब के सेवन के अनुमानों के आधार पर गणना की कि 2020 में 1.34 अरब लोगों ने हानिकारक मात्रा में इसका सेवन किया। शोधकर्ताओं ने कहा कि हर क्षेत्र में, असुरक्षित मात्रा में शराब पीने वाली आबादी का सबसे बड़ा वर्ग 15-39 साल के आयु वर्ग के पुरुष थे और इस आयु वर्ग के लोगों को शराब पीने से कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं होता बल्कि कई स्वास्थ्य जोखिम होते हैं।

5.7 की तीव्रता के भूकंप के झटकों से थर्राया इक्काडोर, बिजली की तार गिरने से एक किशोर की मौत

क्वीटो ।इक्काडोर के तट पर बृहस्पतिवार को 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान एक किशोर पर बिजली की तार गिरने से उसकी मौत हो गई। 'यूएस जियोलॉजिकल सर्वे' के अनुसार, भूकंप का केंद्र ग्वायाकिल बंदरगाह से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में करीब 80 किलोमीटर की गहराई पर था। इक्काडोर के भूभौतिकीय संस्थान के अनुसार, देश के अधिकतर हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि, पहाड़ी क्षेत्रों में इसका बेहद मामूली असर दिखा। तटीय ग्वायस प्रांत में सिमोन बोलिवर कैंटन के मेयर जॉर्ज वेरा ने बताया कि 16 वर्षीय एक किशोर की मौत हो गई। बिजली की एक तार उस पर गिर गई थी। इस संबंध में उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

जापान के प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे की मृत्यु के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया

तोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा ने पूर्व नेता शिंजो आबे की मृत्यु के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा नहीं होने को बृहस्पतिवार को जिम्मेदार ठहराया। जापान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार आबे की शुक्रवार को पश्चिमी जापान के नारा में चुनावी सभा के दौरान भाषण देते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोलीबारी की तस्वीरों और वीडियो से पता चलता है कि बंदूकधारी चुनावी सभा में आबे के करीब आया हुआ था। किशिदा ने कहा कि राष्ट्रीय जन सुरक्षा आयोग और राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या गलत हुआ और वे आवश्यक कदम उठायेंगे। उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि सुरक्षा उपायों में समस्याएं थीं।'' उन्होंने कहा, ''मैं उनसे अन्य देशों के उदाहरणों का अध्ययन करते हुए, विस्तृत जांच करने और कमियों को दूर करने आग्रह करता हूं।'' उन्होंने इस साल के अंत में आबे के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी योजना की भी घोषणा की। पुलिस ने घटनास्थल पर ही हमलावर तेत्सुया यामागामी (41) को पकड़ लिया था। वह जापान की नौसेना का पूर्व सदस्य है। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि उसने जांचकर्ताओं को बताया कि आबे और एक धार्मिक समूह के बीच संबंधों की अफवाह के कारण उसके मन में नफरत पैदा हो गई थी और यही कारण था कि उसने पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी। आबे संसदीय चुनावों में एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में भाषण दे रहे थे, जब उन्हें गोली मार दी गई थी। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी और इसके गठबंधन साझेदार ने संसदीय चुनाव में रविवार को बड़ी जीत दर्ज की थी। संदिग्ध ने कथित तौर पर पुलिस को बताया था कि उसने एक दिन पहले दूसरे शहर में एक भाषण के दौरान आबे को गोली मारने का इरादा छोड़ दिया था क्योंकि प्रवेश द्वार पर बैग की जांच की जा रही थी। आबे का मंगलवार को तोक्यो में अंतिम संस्कार किया गया था।

बलूचिस्तान के आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का अपहरण करने के बाद हत्या की

इस्लामाबाद/कराची। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान सूबे में सक्रिय आतंकवादियों ने सेना के एक अधिकारी का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। दरअसल, इस सप्ताह की शुरुआत में आतंकवादियों द्वारा अगवा किए गए पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी का शव बृहस्पतिवार को अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक राजमार्ग पर मिला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नामक संगठन ने पाकिस्तानी सेना के कर्नल लइक बेग मिर्जा की हत्या की जिम्मेदारी ली है।

स्वीडन में एक पूर्व ईरानी अधिकारी के खिलाफ फैसला आने के बाद उत्साहित लोग।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की दौड़ में दूसरे चरण में जीत के साथ सुनक की पकड़ और मजबूत

लंदन। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में ऋषि सुनक ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। बृहस्पतिवार को दूसरे चरण के मतदान में वह 101 मतों के साथ पुनः विजयी हुए हैं। टोरी पार्टी के नेतृत्व की इस स्पर्धा में अब केवल पांच उम्मीदवार बचे हैं। भारतीय मूल की एटॉर्नी जनरल सुएला ब्रेवरमैन सबसे कम 27 मत प्राप्त होने के साथ ही इस दौड़ से बाहर हो गयी हैं। सांसदों द्वारा दूसरे चरण के मतदान के बाद आगे बढ़ती इस स्पर्धा में सुनक के अलावा व्यापार मंत्री पेनी मोरडुएंट (83 वोट), विदेश मंत्री लिज ट्रस (64 वोट), पूर्व मंत्री केमी बाडेनोक (49 वोट) और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता टॉम टुगेनडैट (32 वोट) बचे हैं। 1922 कमेटी के अध्यक्ष ग्राहम ब्रेडी ने जैसे ही टोरी सांसदों द्वारा 356 वोट डाले जाने के बाद ताजा परिणाम पढ़ा, उसके बाद सुनक ने कहा कि वह उनका समर्थन करने वाले सहयोगियों के प्रति आभारी हैं। उन्होंने कहा, ''मैं अपने देश की सेवा में वो सबकुछ देने को तैयार हूं जो मेरे पास है। हम मिलकर विश्वास कायम कर सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और देश को पुनः संगठित कर सकते हैं।'' कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के बीच मतदान के अगले पांच चरण पूरे होने के साथ आगामी बृहस्पतिवार तक केवल दो नेता इस दौड़ में रह जाएंगे।

रानिल विक्रमसिंघे ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष समिति की नियुक्त

बोले- हम लोकतंत्र को नष्ट करने की नहीं देंगे अनुमति

कोलंबो। (एजेंसी)।

श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। इसी बीच कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें सांसदों के लिए ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त कर सकें। उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। हम किसी भी समूह को संसद में लोकतंत्र को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे। साथ ही ऐसे समूह भी हैं जो लोकतंत्र का दमन कर फासीवादी तरीकों से देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि संसद के पास ऐसे लोगों ने सुरक्षाबलों के दो हथियारों को गोलियां के साथ चुरा लिया है। उन्होंने बताया कि सेना के 24 सदस्य घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 आज गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विद्रोहियों और प्रदर्शनकारियों के बीच एक बड़ा अंतर है। शुरू से ही संघर्ष में शामिल कई लोगों ने तोड़फोड़ की इन हरकतों का विरोध किया है।

विशेष समिति नियुक्त की

उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, मैंने एक विशेष समिति नियुक्त की है जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पुलिस महानिरीक्षक और तीनों सशस्त्र बलों के कमांडर शामिल हैं। उन्हें बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कानूनी कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मैं दो और निर्णय लूंगा। राष्ट्रपति को संबोधित करने के लिए महामहिम शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के झंडे को खत्म किया जाएगा, क्योंकि देश को सिर्फ एक झंडे के इर्द-गिर्द जुटना चाहिए और वह राष्ट्रीय ध्वज है।

कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त

प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने गोटबाया राजपक्षे का उत्तराधिकारी चुने जाने तक अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शुक्रवार को शपथ ग्रहण की। उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां संसद को देने के मकसद से संविधान के 19वें संशोधन को बहाल करने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया। सिंगापुर पहुंचे राजपक्षे ने अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने को ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा पत्र भेजा। अभयवर्धने ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें इस्तीफा पत्र बृहस्पतिवार को ही मिल गया तथा उन्होंने उसे मंजूर कर लिया है।

पाकिस्तान की अदालत ने धन शोधन मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे को भगोड़ा घोषित किया

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के छोटे बेटे सुलेमान शहबाज और एक अन्य व्यक्ति को धन शोधन के एक मामले में शुक्रवार को भगोड़ा घोषित किया। 'डॉन' अखबार की खबर के मुताबिक, लाहौर विशेष अदालत (सेंट्रल- एक) ने सुलेमान और ताहिर नकवी को भगोड़ा घोषित कर दिया, क्योंकि वे पेशी के लिए बुलाए जाने के बावजूद पेश नहीं हुए। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने नवंबर, 2020 में शहबाज और उनके बेटों हमजा तथा सुलेमान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया था। सुलेमान और नकवी के खिलाफ 28 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये थे। उसी सुनवाई में, अदालत ने एक अन्य संदिग्ध मलिक मकसूद के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसका पिछले महीने संयुक्त अरब अमीरात में निधन हो गया था। एफआईए ने 11 जून को सुलेमान, नकवी और मकसूद के लिए जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एफआईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वारंट पर अमल नहीं किया जा सकता क्योंकि सुलेमान अपने पते पर मौजूद नहीं थे और विदेश चला गये हैं। शुक्रवार की सुनवाई में अदालत ने सुलेमान और नकवी की संपत्तियों के साथ-साथ मकसूद के मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी मांगी। अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज को सुनवाई में शामिल होने से एक बार की छूट देने का अनुरोध भी स्वीकार कर लिया, लेकिन निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई में अदालत के सामने पेश हों। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। एफआईए ने दिसंबर, 2021 में चीनी घोटाला मामले में 16 अरब रुपये की राशि के धन शोधन में कथित संलिप्तता के लिए शहबाज और हमजा के खिलाफ एक विशेष अदालत में चालान पेश किया था।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन जाएंगे वेस्ट बैंक, फलस्तीनियों के लिए खास पेशकश की संभावना नहीं

यरुशलम। (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन फलस्तीनी नेताओं के साथ बातचीत के लिए शुक्रवार को इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक जाएंगे, तो उनके पास शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अमेरिकी धन मुहैया कराने के अलावा कोई खास पेशकश नहीं होगी। बाइडन द्वारा वित्तीय सहायता के तौर पर 31.6 करोड़ डॉलर की घोषणा करने की उम्मीद है जिनमें से लगभग एक तिहाई को अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, फलस्तीनियों के लिए संचार संपर्क प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता को लेकर भी वह बात कर सकते हैं। बाइडन स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र के लिए अपना समर्थन जता सकते हैं, लेकिन इसके लिए आगे का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। गंभीर शांति वार्ता का अंतिम दौर एक दशक से भी अधिक समय पहले अटक गया था, जिससे लाखों फलस्तीनी वेस्ट बैंक में इजराइली सैन्य शासन के अधीन रह रहे हैं। इजराइल की निवर्तमान सरकार ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा में आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री यायर लापिड के पास शांति वार्ता करने का जनादेश नहीं है और एक नवंबर का चुनाव दक्षिणपंथी सरकार को सत्ता में ला सकता है, जो फलस्तीनी राष्ट्र के विरोध में है। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास फलस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं की तुलना में यथास्थिति बनाए रखने के ज्यादा समर्थक हैं।

अमेरिकी संसद में प्रतिबंधों से भारत को खास छूट दिलाने वाला विधेयक पारित

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने भारत को रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए सीएटीएसए प्रतिबंधों से खास छूट दिलाने वाले एक संशोधित विधेयक को बृहस्पतिवार को पारित कर दिया। भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना द्वारा पेश किए गए इस संशोधित विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट' (सीएटीएसए) से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून (एनडीएए) पर सदन में चर्चा के दौरान बृहस्पतिवार को ध्वनि मत से यह संशोधित विधेयक पारित कर दिया गया। खन्ना ने कहा, ''अमेरिका को चीन के बढ़ते आक्रामक रूख के मद्देनजर भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारत कॉकस के उपाध्यक्ष के तौर पर मैं हमारे देशों के बीच भागीदारी को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने पर काम कर रहा हूं कि भारतीय-चीन सीमा पर भारत अपनी रक्षा कर सकें।'' उन्होंने कहा, ''यह संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मुझे यह देखकर गर्व हुआ कि इसे दोनों दलों के समर्थन से पारित किया गया है।''

सदन में अपनी टिप्पणियों में खन्ना ने कहा कि अमेरिका-भारत भागीदारी से ज्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका के रणनीतिक हित में और कुछ भी इतना जरूरी नहीं है। विधेयक में कहा गया है कि 'यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीस' (आईसीईटी) दोनों देशों में सरकारों, शैक्षणिक समुदाय और उद्योगों के बीच करीबी साझेदारी विकसित करने के लिए एक स्वागत योग्य और आवश्यक कदम है ताकि कृत्रिम बुद्धिमता, क्वांटम कम्प्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर विनिर्माण में नवीनतम प्रगति को अपनाया जा सकें। इसमें कहा गया है कि इंजीनियर और कम्प्यूटर वैज्ञानिकों के बीच ऐसी भागीदारी यह सुनिश्चित करने में अहम है कि अमेरिका और भारत के साथ ही दुनियाभर में अन्य लोकतांत्रिक देश नवोन्मेष और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे सकें, ताकि ये रूस और चीन की प्रौद्योगिकी को पछाड़ सकें। वर्ष 2017 में पेश सीएटीएसए के तहत रूस से रक्षा और खुफिया लेन-देन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसे 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मॉस्को के कथित हस्तक्षेप के जवाब में लाया गया था।

भारत की मदद से कम हुए श्रीलंका में सब्जियों के दाम ! मई में हजार रुपए प्रतिकिलो में मिल रही थी शिमला मिर्च और गोभी

कोलंबो। (एजेंसी)।

श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट छाया हुआ है। ऐसे में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है और खाद्य पदार्थ की कीमतों से जनता बेहद परेशान है। इसी बीच भारत अपने पड़ोसी धर्म को निभा रहा है और लगातार श्रीलंका के लोगों और उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पड़ोसी देश की मदद में जुटा हुआ है। श्रीलंका में भारी महंगाई के बीच कुछ सब्जियों की कीमतों में पिछले महीने की तुलना में कमी देखी गई है।

आपको बता दें कि भारत ने श्रीलंका को कीटनाशक और यूरिया की सप्लाई की थी। ताकि वहां पर सब्जियों को और अधिक समय के लिए बचाया जा सकें। साथ ही उत्पादन क्षमता भी पहले से बेहतर हो और ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। इसके अलावा ईंधन भी श्रीलंका भेजा जा रहा है।

सब्जियों के दाम में हुई थोड़ी

कटौती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीलंका में आलू और प्यास जैसी बेहद जरूरी सब्जियों के दाम में लगातार इजाफा हो रहा था लेकिन भारत की तरफ से ईंधन भेजे जाने के बाद यहां पर आलू और प्यास के दामों में थोड़ी कटौती हुई है। साथ ही साथ भारत से आने वाली सब्जियों के दाम भी यहां की तुलना में कम है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि मई में प्याज 340 रुपए प्रतिकिलो मिल रही थी, जो अब 260 रुपए प्रतिकिलो की दर से मिल रही है।

टमाटर की बात करें तो मई में इसकी कीमत 900 रुपए प्रतिकिलो तक पहुंच गई थी लेकिन अब 380 रुपए प्रतिकिलो के आस-पास है। शिमला मिर्च, गोभी की कीमतें तो मई में हजार पार थीं लेकिन अब यह 700-800 रुपए के आसपास मिल रही हैं।

सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी

श्रीलंका में आजादी के बाद गहराए अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट को लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति भवन में कब्जा कर लिया था। जहां से गोटबाया राजपक्षे अपनी पत्नी के साथ भाग गए थे और फिर उनके देश छोड़कर मालदीव जाने की वजह से गुस्साएं प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कब्जा कर लिया था। हालांकि बीते दिनों गोटबाया राजपक्षे के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाया और जमकर पटाखे फोड़े।

महाराष्ट्र: बारिश संबंधी घटनाओं में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत

मुंबई। महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक, यह संख्या एक जुलाई से 14 जुलाई के बीच दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में तीन लोगों की मौत हुई, जिनमें बुलढाणा, नासिक और नंदूरबार जिलों में एक-एक व्यक्ति की हुई मौत शामिल है। राज्य में बाढ़, आकाशीय बिजली, भूस्खलन और पेड़ गिरने समेत बारिश संबंधी अन्य घटनाओं में 102 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र के 20 गांव भारी बारिश से प्रभावित हैं और कम से कम 3,873 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। उल्लेखनीय है कि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों समेत राज्य के कई भागों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश जारी है।

देश में कावड़ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट रिपोर्ट के आधार

नई दिल्ली । कावड़ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाजरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट रिपोर्ट के आधार पर जारी हुई है। सूत्रों के मुताबिक कावड़ यात्रा के दौरान कट्टरपंथियों से खतरे का अंदेशा है। इसमें राज्य सरकारों से कहा गया है कि कावड़ यात्रा को लेकर किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल तैनात करे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों को कावड़ यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिए हैं। रेलवे बोर्ड को भी ट्रेनों में खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि 15 जुलाई से श्रावण माह शुरू होते ही देशभर में शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। अलग-अलग राज्यों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कई सुविधाओं के साथ सुरक्षा इंतजाम भी पुख्ता हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय ने कट्टरपंथी तत्वों से खतरे की आशंका जताकर राज्य सरकारों को कांवड़ियों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं. श्रावण माह में भक्त पवित्र नदियों का जल कंधे पर रखे कांवड़ में लेकर भगवान शिव के विभिन्न मंदिरों तक पहुंचते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। गौरतलब है कि कोरोना के कारण 2 साल के अंतराल के बाद कांवड़ यात्रा हो रही है। अधिकारियों का अनुमान है कि करीब 1 पखवाड़े तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान कम से कम 4 करोड़ कांवड़िए सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश में पवित्र नदी का जल लेने पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के कांवड़िए हरिद्वार और ऋषिकेश जाते हैं। इसके अलावा झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां श्रावण माह में भगवान शिव को जल चढ़ाने की परम्परा है। यहां करोड़ों की संख्या में शिवभक्त पहुंचते हैं।

काबुल में डर के साए में गुजारे दिन-रात, अफगानिस्तान से भारत आए सिख ने सुनाई खौफनाक दास्तां

नई दिल्ली । अफगान सिख 27 वर्षीय राजिंदर सिंह के लिए बीता साल किसी दु-स्वप्न से कम नहीं था, जब उन्होंने तालिबान के कब्जे वाले काबुल में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया और दिन-रात डर के साए में समय बिताया। राजिंदर और उनकी पत्नी उन 21 अफगान सिखों में शामिल हैं, जो गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। भारत सरकार अफगानिस्तान से अल्पसंख्यकों को निकालने का अभियान चला रही है, जिसके तहत ये लोग यहां पहुंचे। सिंह की सात माह की गर्भवती पत्नी ने चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में सितंबर 2021 को अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया था। राजिंदर ने कहा काबुल शहर कब्रगाह में तब्दील हो गया है और उस समय किसी भी अस्पताल तक पहुंच पाना नामुमकिन-सा था। मेरी पत्नी सात माह की गर्भवती है, जब हमने अपने बच्चे को खो दिया था। कोई डॉक्टर नहीं था, जांच कराने का कोई तरीका नहीं दिखा। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद काबुल में अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदायों के ज्यादातर लोगों ने एक गुरुद्वारे में शरण ले ली थी। राजिंदर ने कहा हमें दो महीनों तक गुरुद्वारे की चारदीवारी से आगे कुछ भी देखने को नहीं मिला। अफगानिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमारी जान पर लगातार खतरा बना हुआ था। काबुल में गुरुद्वारा दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह कर्ते परवान पर 18 जून को हमला हुआ था। गुरुद्वारे में कई अफगान सिख अल्पसंख्यकों ने शरण ली हुई थी। राजिंदर ने कहा मेरा घर गुरुद्वारे के बिल्कुल पीछे था। जब गुरुद्वारे पर हमला हुआ तो हमें अपने घर पर भी गोलियों की आवाजें सुनायी दीं। उस समय ऐसा कोई नहीं था जिससे हम मदद मांग सकते थे। फिर भारत सरकार ने हमारी मदद की और हम वहां से निकल सके। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी), इंडियन वर्ल्ड फोरम और केन्द्र सरकार की मदद से 21 अफगान सिखों को काबुल से यहां लाया गया। इनमें तीन बच्चे और एक शिशु भी शामिल हैं। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंदोक ने कहा हम इंडियन वर्ल्ड फोरम की ओर से हरसंभव मदद कर रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए सभी तरह की व्यवस्था की गयी है। हम अफगानिस्तान से भारत तक उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 130 अफगान हिंदू और सिख अब भी अफगानिस्तान में हैं और भारत सरकार के पास वीजा जारी करने के लिए करीब 60 आवेदन लंबित है। उन्होंने कहा तालिबान सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। उनमें रोष है। वे नहीं चाहते कि अफगान सिख और हिंदू देश छोड़कर जाए क्योंकि इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा।

रक्षामंत्री राजनाथ ने लांच किया 17ए फ्रिगेट दूनागिरी, कहा यह हमारी आत्मनिर्भर होती नौसेना का प्रतीक

नई दिल्ली (लेह)। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) में प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट 'दूनागिरी' के शुभारंभ समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने सभी पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। श्रीलंका जिस कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, उससे हम सब वाकिफ हैं। कोविड और यूक्रेनियन संघर्ष के चलते भारत भी प्रभावित रहा है, उसके बाद भी हम श्रीलंका की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि दूनागिरी, का नाम उत्तराखंड में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। 'दूनागिरी' पी17ए फ्रिगेट्स का चौथा जहाज है। ये बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ पी17 फ्रिगेट्स (शिवालिक क्लास) के फॉलो-ऑन हैं। 'दूनागिरी' पूर्ववर्ती 'दूनागिरी', लिएंडर क्लास एएसडब्ल्यू फ्रिगेट का पुनर्जन्म है, जो 05 मई 1977 से 20 अक्टूबर 2010 तक अपनी 33 वर्षों की सेवा में कई चुनौतीपूर्ण संचालन और बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में शामिल रहा था। पी17ए प्रोजेक्ट के पहले दो जहाजों को 2019 और 2020 में एमडीएल और जीआरएसई में लॉन्च किया गया था। तीसरा जहाज (उदयगिरी) इस साल की शुरुआत में 17 मई 22 को एमडीएल में लॉन्च किया गया था। इतने कम समय में चौथे जहाज का लॉच आत्मनिर्भर होती नौसेना की बढ़ती ताकत का प्रमाण है।

इंजन में कंपन महसूस होने के बाद जयपुर में उतारनी पड़ी इंडिगो की दिल्ली-वडोदरा फ्लाइट

नई दिल्ली । विमानन कंपनी 'इंडिगो' के दिल्ली-वडोदरा विमान के इंजन में कुछ सेकंड के लिए कंपन महसूस किए जाने के बाद पायलट ने एहतियातन उसे जयपुर में उतारने का फैसला किया। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुरुवार को हुई घटना की डीजीसीए जांच कर रहा है। विमानन कंपनी 'स्पाइसजेट' भी इन दिनों डीजीसीए के जांच के दायरे में है। 'स्पाइसजेट' के विमानों में 19 जून से तकनीकी समस्या के कम से कम आठ मामले सामने आने के बाद डीजीसीए ने छह जुलाई को उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था। विमानन नियामक का कहना है कि वाहक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई सेवाओं का संचालन करने विफल रहा है।

कांग्रेस का केन्द्र सरकार पर हमला, कहा- प्रधानमंत्री मोदी रुपये के लिए हानिकारक हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)।

कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 80 तक पहुंच जाने को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुपये के लिए हानिकारक हैं।' उल्लेखनीय है कि बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 80 प्रति डॉलर के ऐतिहासिक निचले स्तर के पास पहुंच गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के कुछ अन्य नेताओं के अतीत के कुछ बयानों से जुड़ा वीडियो जारी करते हुए संवाददाताओं से कहा, ''लोगों को याद रहना चाहिए कि 2014 के पहले क्या कहा गया। कहा गया था कि भाइयों और बहनों, रुपया उसी देश का गिरता है, जहां की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई हो! यह भी कहा गया था कि कभी-कभी तो लगता है दिल्ली (केंद्र) सरकार और रुपये के बीच में कॉम्पटिशन चल रहा है - किसकी आबरू तेज़ी से गिरती चली जा रही है - कौन और आगे जाएगा?''

सुप्रिया ने पूर्व विदेश मंत्री और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहीं दिवंगत सुषमा स्वराज के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'रुपया सिर्फ़ काग़ज़ का टुकड़ा नहीं होता, सिर्फ़ करेन्सी नहीं होती-इसके साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है। जैसे जैसे रुपया गिरता है देश की प्रतिष्ठा गिरती है।'' उन्होंने दावा किया, ''जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, मोदी जी की कृपा से उनके स्वघोषित अमृतकाल में वो दिन भी देश ने देख ही लिया। भारत का रुपया अमेरिकी डॉलर के मुक़ाबले 80 पार कर गया।'' सुप्रिया ने कहा, ''यह वही रुपया है, जिससे प्रधानमंत्री की आबरू और प्रतिष्ठा जुड़े होने का दावा खुद मोदी जी करते थे। पर आज तो डर यह है कि जिस तेज़ी से रुपया गिर रहा है - कहीं पेट्रोल की तरह, यहां भी शतक की तैयारी तो नहीं?'' कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार, ''2014 के पहले रुपये की मज़बूती के लिए मोदी ज़रूरी है का दावा करने वाले प्रधानमंत्री तो हमारे रुपए के लिए बड़े हानिकारक साबित हुए। इन तथाकथित मज़बूत प्रधानमंत्री ने इतिहास में रुपये को सबसे कमजोर बना दिया।''सुप्रिया ने सवाल किया, ''पिछले 6 महीने में रुपया 7 प्रतिशत से ज़्यादा गिरा है, कभी कोरोना कभी यूक्रेन रूस की जंग के पीछे कब तक छिपते रहेंगे प्रधानमंत्री जी?'' उन्होंने कहा कि 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 58 थी और पिछले आठ वर्षों में 80 तक पहुंच गई। कांग्रेस नेता ने कहा, ''2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनने के समय डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत 45 थी और 10 साल बाद यह 58 तक पहुंची। यानी 10 वर्षों में 13 अंकों की गिरावट आई, लेकिन मोदी सरकार के आठ वर्षों में 22 अंकों की गिरावट आई है।'' उन्होंने दावा किया, ''आज यह स्वीकारना पड़ेगा कि कमजोर रुपये का सबसे बड़ा कारण ध्वस्त अर्थव्यवस्था- बेलगाम महंगाई है। सरकार हर बार की तरह दिशाहीन ही नज़र आती है। डर तो यह लगता है कहीं 80, 90 पूरे 100 करने की मंशा तो नहीं है साहेब की? मोदी रुपये के लिए हानिकारक हैं।'' सुप्रिया ने यह आरोप भी लगाया कि निवेशकों का इस सरकार में भरोसा नहीं रहा।

कोविड संक्रमण से उबर रहे हैं स्टालिन, प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा हाल-चाल

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोरोना वायरस संक्रमण से उबर रहे हैं तथा उन्हें कुछ और दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी गयी है। उनका इलाज कर रहे अस्पताल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टालिन से फोन पर बात की और उनका हाल-चाल पूछा। मुख्यमंत्री स्टालिन 12 जुलाई को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे और उन्हें बृहस्पतिवार को जांच के लिए यहां कावेरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने बुलेटिन में कहा, ''जांच पूरी हो गयी है और कोविड के उपचार के प्रोटोकॉल के अनुसार दवाएं दी गयी हैं। मुख्यमंत्री बीमारी से उबर रहे हैं और अभी उनकी हालत सही है। उन्हें कुछ और दिन आराम करने की सलाह दी गयी है।'' राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और उनका हाल-चाल पूछा। इसमें कहा गया है, ''मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि वह स्वस्थ हो रहे हैं।

कैबिनेट की आखिरी बैठक में औरंगाबाद का नाम बदलना अवैध था, इसे फिर से मंजूरी देंगे: एकनाथ शिंदे

मुंबई। (एजेंसी)।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि पूर्ववर्ती महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलने के संबंध में लिया गया फैसला अवैध था, क्योंकि सरकार अल्पमत में थी और इसे कैबिनेट की अगली बैठक में फिर से मंजूरी दी जाएगी। उद्धव ठाकरे नीत एमवीए सरकार ने 29 जून को कैबिनेट की आखिरी बैठक में मध्य महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नाम छत्रपति शिवाजी के बड़े बेटे छत्रपति संभाजी के नाम पर 'संभाजीनगर' करने की घोषणा की थी। इसके कुछ घंटे बाद ही ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

शिंदे ने अगले दिन 30 जून को भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री ने यहां एक कार्यक्रम में दावा किया, 'एमवीए सरकार ने अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का फैसला तब किया, जब सरकार अल्पमत में आ गई थी। (ऐसी स्थिति में) कैबिनेट की बैठक करना अवैध था।' शिंदे ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने कई दशक पहले औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने का ऐलान किया था। औरंगाबाद का नाम मुगल बादशाह औरंगज़ेब के नाम पर रखा गया है।

उन्होंने कहा, 'पहले से ही संभाजीनगर नाम है। हम कैबिनेट की अगली बैठक में इसे मंजूरी देंगे, जो इस फैसले को कानूनी तौर पर सुरक्षित करेगा।' शिंदे ने यह भी कहा कि उन्होंने शिवसेना के नेतृत्व के खिलाफ बगावत पार्टी और इसके कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए की। उन्होंने कहा, 'तीन दलों के गठबंधन वाली सरकार में हमारा मुख्यमंत्री होने के बावजूद हमें राजनीतिक रूप से कुछ नहीं मिला। हम नगर पंचायत चुनाव में चौथे स्थान पर रहे।' वह शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे। शिंदे ने दावा किया कि राज्य के लोगों ने विद्रोह करने के उनके फैसले को स्वीकार किया है, क्योंकि यह राज्य के हित में था।

इस बीच, औरंगाबाद में शिवसेना के नेता और पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे ने चेताया कि अगर शहर का नाम एक महीने के अंदर नहीं बदला गया तो पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन शुरू कर देंगे। वह ठाकरे के खेमे के हैं। खैरे ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि शिंदे नीत सरकार ने नाम बदलने पर रोक लगा दी है, जो छत्रपति संभाजी का अपमान है। शहर के हवाई अड्डे का नाम भी एक महीने में संभाजी के नाम पर रखने की मांग करते हुए खैरे ने कहा, 'भाजपा जब 2014-19 तक सत्ता में थी, तब उसने नाम क्यों नहीं बदला? भाजपा नीत केंद्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम (छत्रपति संभाजी के नाम पर रखने) का प्रस्ताव तक पारित नहीं किया।

उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में लेकिन सरकार का ध्यान जनता के हितों पर नहीं: अखिलेश यादव

लखनऊ। (एजेंसी)।

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सूखे की चपेट में आ गया है लेकिन सरकार का जनता के हितों की ओर ध्यान नहीं है। यहां सपा मुख्यालय से जारी बयान में यादव ने कहा कि बारिश न होने से खरीफ की बुवाई रुकी हुई है और सरकार के कथित पौधारोपण अभियान पर भी सूखे का साया मंडराने लगा है एवं लगभग पूरे प्रदेश में स्थिति काफी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि समय से बरसात नहीं होने से धान की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है तथा बहुत जगह तो खरीफ की बुवाई ही रूक गई है। बिजली संकट की चर्चा करते हुए यादव ने कहा कि राज्य में बिजली भी उपलब्ध नहीं है और गांवों में 10 घंटे भी बिजली की उपलब्धता नहीं है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा राज में बुंदेलखंड की बहुत उपेक्षा हुई है जबकि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में बुंदेलखंड में विकास के जो कार्य हुए उससे पूरा बुन्देलखण्ड लाभान्वित हुआ। यादव ने दावा किया कि भाजपा बस नफरत की राजनीति के सहारे सत्ता से चिपके रहना ही जानती है एवं उसकी नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश विकास के हर पायदान पर नीचे फिसलता जा रहा है।

राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों को हरे रंग के और विधायकों को गुलाबी रंग के मतपत्र मिलेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)।

राष्ट्रपति चुनाव के तहत आगामी 18 जुलाई को होने वाले मतदान के दौरान सांसदों और विधायकों को अलग-अलग रंग के मतपत्र दिए जाएंगे। सांसदों को जहां हरे रंग के मतपत्र दिए जाएंगे, वहीं विधायकों को गुलाबी रंग के मतपत्र मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों का वोट उस राज्य की आबादी पर निर्भर करता है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बार एक सांसद के मत की कीमत 700 है। चूंकि अलग-अलग रंग के मतपत्र होगा, लिहाजा निर्वाचन अधिकारियों को मतों की गिनती में आसानी होगी। मतपत्रों में दो कॉलम छपे हुए हैं। पहले कॉलम में उम्मीदवारों के नाम हैं, तब दूसरे में निर्वाचक मंडल के सदस्यों को प्रत्येक उम्मीदवार के लिए वरीयता क्रम लिखने की जगह निर्धारित की गई है। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की उम्मीदवार हैं,तब विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं हैं, इसलिए, वे चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं होते। इसी तरह, विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदाता नहीं होते हैं।

महुआ मोइत्रा का केंद्र पर तंज, 'क्यों ना संसद परिसर से गांधी जी के प्रतिमा को ही हटा दिया जाए'

नई दिल्ली (एजेंसी)।

संसद के मानसून सत्र से पहले जारी आदेशों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कुछ दिन पहले संसद में सांसदों के द्वारा बोले जाने वाले कुछ शब्दों को असंसदीय शब्दों की श्रेणी में रखे जाने की बात कही गई थी। अब एक नए आदेश में आ गया है। आदेश में कहा गया है कि भवन परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह के लिए नहीं किया जा सकता। इसको लेकर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। हाल में ही मां काली को लेकर अपनी टिप्पणी पर विवादों में आई तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि क्यों ना संसद परिसर से गांधी जी के प्रतिमा को ही हटा दिया जाए और संविधान से आर्टिकल 19 (1) मिटा दिया जाए। इससे पहले कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, 'विषगुरू का ताजा प्रहार...धरना मना है।'' भवन परिसर का इस्तेमाल धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिये नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन में यह बात कही गई है। धरना, प्रदर्शन को लेकर यह बुलेटिन ऐसे समय में सामने आया है जब एक दिन पहले ही लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी असंसदीय शब्दों के संकलन को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा था। मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी द्वारा जारी बुलेटिन में इस विषय पर सदस्यों से सहयोग का अनुरोध किया गया है। वहीं, एक दिन पहले ही, संसद में बहस आदि के दौरान सदस्यों द्वारा बोले जाने वाले कुछ शब्दों को असंसदीय शब्दों की श्रेणी में रखे जाने के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए कहा था कि सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब असंसदीय माने जाएंगे। हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया था कि संसदीय कार्यवाही के दौरान किसी शब्द के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं किया गया है बल्कि उन्हें संदर्भ के आधार पर कार्यवाही से हटाया जाता है तथा सभी सदस्य सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकसभा सचिवालय ने ''असंसदीय शब्द 2021 '' शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिसमें जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चाण्डाल चौकड़ी, गुल खिलाए, तानाशाह, भ्रष्ट, ड्रामा, अक्षम, पिट्ठू जैसे शब्द शामिल हैं।

दलाई लामा का लद्दाख में गर्मजोशी भरा स्वागत देखकर चीन को लग गयी 'लाल वाली मिर्ची'

ओटावा (एजेंसी)।

तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा आज केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की यात्रा पर पहुँचे जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनका यहां एक महीने तक रुकने और कई आयोजनों में भाग लेने का कार्यक्रम है। दलाई लामा के लद्दाख में हो रहे स्वागत को देखकर चीन को मिर्ची लग गयी है और उसने तिब्बती आध्यात्मिक नेता की इस यात्रा पर आपत्ति जता दी है लेकिन भारत ने कहा है कि यह यात्रा ''पूरी तरह से धार्मिक'' है और किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक शीर्ष सरकारी पदाधिकारी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि दलाई लामा सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं क्योंकि वह पहले भी कई बार लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। सरकारी पदाधिकारी ने कहा, ''दलाई लामा एक आध्यात्मिक नेता हैं और उनकी लद्दाख यात्रा पूरी तरह से धार्मिक है। उनके दौरे पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए।''

बताया जा रहा है कि पूर्वी लद्दाख में टकराव के कई बिंदुओं पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सैन्य गतिरोध के बीच आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की लद्दाख यात्रा से चीन नाराज हो गया है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि इस महीने की शुरुआत में चीन ने दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत को चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तिब्बत से संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। वहीं भारत ने चीन की आलोचना को खारिज करते हुए कहा था कि दलाई लामा देश के सम्मानित अतिथि हैं। गौरतलब है कि 1959 में तिब्बत से पलायन के बाद से दलाई लामा भारत में रह रहे हैं। दलाई लामा का असली नाम तेंज़िन ग्यात्सो है और उन्हें 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था।

देखा जाये तो पिछले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के बाहर दलाई लामा की यह पहली यात्रा है। एक दिन पहले वह जम्मू में थे जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके अनुयायी भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। इस दौरान 87 वर्षीय आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने पत्रकारों से कहा, 'चीन के कुछ कट्टरपंथी मुझे अलगाववादी और सुधार का विरोधी समझते हैं और हमेशा मेरी आलोचना करते हैं। लेकिन अब अधिक संख्या में चीन के लोगों को यह अहसास हो रहा है कि दलाई लामा स्वतंत्रता नहीं मांग रहे हैं और उनकी इच्छा सिर्फ इतनी है कि चीन (तिब्बत को) सार्थक स्वायत्तता दे और तिब्बती बौद्ध संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित करे।÷ उनकी यात्रा को लेकर चीन की आपत्ति के बारे में पूछे जाने पर दलाई लामा ने कहा, 'यह सामान्य है। चीन के लोग ऐतराज़ नहीं कर रहे हैं.... अधिक संख्या में लोग तिब्बती बौद्ध धर्म में रुचि दिखा रहे हैं।' उन्होंने कहा कि चीन के कुछ विद्वानों को अहसास हो रहा है कि तिब्बती बौद्ध धर्म बहुत वैज्ञानिक है। चीज़ें बदल रही हैं।÷ भारत और चीन के बीच विवादों पर उन्होंने कहा था कि दोनों देशों को बातचीत से मुद्दे का हल निकालना चाहिए।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

जनहित याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट के नोटिस के बाद निर्वाचन आयोग में हड़कंप की स्थिति

मध्यप्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर पंचायत के उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए

क्रांति समय,सूरत
www.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com

हाईकोर्ट में इस पीआईएल दायर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी की अपील पर ही पिछले साल ही राज्य सूचना आयोग ने पंचायतों के उम्मीदवारों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किया था। अब सूचना आयोग के आदेश का पालन नहीं होने पर शिवानंद द्विवेदी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मजेदार बात यह है कि हाईकोर्ट का नोटिस जारी होते ही आनन फानन रातों-रात जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उम्मीदवारों की जानकारी निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

लेकिन उसके बाद भी ग्राम पंचायत स्तर की कोई भी जानकारी ना तो जिले की वेबसाइट नाही निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

क्या है अन्य राज्यों में व्यवस्था

उड़ीसा राज्य में पंचायत उम्मीदवारों की सारी जानकारियां वहां के जिले के वेब पेज पर उपलब्ध है। बिहार और झारखंड राज्य के कुछ जिलों में यह जानकारियां वेब पेज पर उपलब्ध है। कर्नाटक राज्य में भी नगरीय निकाय से संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी शपथ पत्र आदि उपलब्ध है। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह का कहना है कि जब अन्य राज्य इस जानकारी को उपलब्ध करा सकते हैं तो मध्यप्रदेश क्यों नही। कोरोना के चलते यह और भी जरूरी हो गया है की जानकारियां लोगों को स्वत: वेबसाइट पर उपलब्ध हो। उसके लिए जनता को सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटना पड़े।

18 जुलाई को होगी हाईकोर्ट मे अगली सुनवाई

जून 2021 में दिए सूचना आयोग के इस आदेश का पालन निर्वाचन आयोग और सामान्य प्रशासन विभाग ने नहीं किया तो आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने पत्र लिखकर के दोनों विभागों को आदेश के पालन करने के लिए लिखा लेकिन उसके बाद भी जब जानकारी को वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया गया तो शिवानंद द्विवेदी हाईकोर्ट की शरण में चले गए। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने अगले सप्ताह 18 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब तलब किया है।

क्या था राज्य सूचना आयोग का आदेश?

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्तराहुल सिंह ने जून 2021 में ऐतिहासिक फैसला देते हुए मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव में सभी उम्मीदवारों की सूची और शपथ पत्र वेबसाइट पर पब्लिक के लिए अपलोड करने के निर्देश मप्र राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश के सभी कलेक्टरों को दिए थे। सिंह ने कहा है कि यह जानकारी लोगों का संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए आरटीआई लगाने की भी जरूत नहीं है।

राज्य सूचना आयुक्तराहुल सिंह ने पंचायत चुनाव के समय सभी उम्मीदवारों की जानकारी जनता को उपलब्ध कराने के अपने निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत जनता का संवैधानिक अधिकार माना है।

सिंह ने अपने आदेश में कोरोना संक्रमण के बदलते स्वरूप के चलते पंचायत चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में सूचना के लिए भीड़ कम से कम लगे और जानकारी स्वत: पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को उपलब्ध होने को भी आधार बनाया है।

क्या है पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की जानकारी की वर्तमान व्यवस्था?

वर्तमान में उम्मीदवारों की जानकारी जैसे उनके अपराधिक प्रकरण उनकी शैक्षणिक योग्यता उनके चल अचल संपत्ति की जानकारी पंचायत की रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में चस्पा की जाती है। यानी कि दूरदराज गांव के लोगों को तहसील मे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय तक आकर ही उम्मीदवारों की जानकारी देख सकते हैं। वही चुनाव खत्म होने के बाद जानकारी को लेना टेढ़ी खीर है। चुनाव के बाद आरटीआई में जानकारी मांगने पर अक्सर अधिकारी कहते हैं कि जानकारी सीलबंद लिफाफे में है और सक्षम अधिकारी ही दे सकते हैं और यह सक्षम अधिकारी कौन है इसका खुलासा भी नहीं करते हैं कुल मिलाकर के जानकारी नहीं मिल पाती है।

सूचना आयोग ने इस प्रकरण में सिविल कोर्ट की शक्ति के अधीन जांच की और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया था। जाँच उपरांत सूचना आयोग ने पाया कि मध्य प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा अपने खुद के राजपत्र में हर पंचायत चुनाव में निर्देश जारी किए जाते हैं कि उम्मीदवारों की जानकारी जैसे शपथ पत्र क्रिमिनल रिकॉर्ड, शैक्षणिक योग्यता, संपत्ति की जानकारी जनता के अवलोकन के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट और जिले के वेब पेज पर प्रदर्शित की जाए। इसके अलावा इस जानकारी को जिले के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में प्रदर्शित करने का भी नियम है। पर स्वयं चुनाव आयोग इस नियम का पालन नहीं करता है और ना ही जिले के वेबपेज पर भी यह जानकारी उपलब्ध है।

क्यो मिलनी चाहिए पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की जानकारी ?

राज्य सूचना आयुक्तराहुल सिंह का मानना है कि पंचायत चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पर जानकारी प्रदर्शित होने से बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी मिल पाती है। वेबसाइट पर आने पर अब सभी लोग इसका अवलोकन कर सकते हैं। जैसी कसावट और पारदर्शिता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में होती है वैसे ही पंचायत चुनाव में भी होनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जानकारी स्वत: वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाती है और इसके लिए वोटर्स को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है और क्यों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहती है तो बाद में भी आरटीआई लगाने की जरूत नहीं पड़ती है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह सिंह का कहना है कि गांव के वोटर्स को भी यह जानने का हक है कि उनके जनप्रतिनिधियों ने चुनाव दर चुनाव कितनी संपत्ति अर्जित की है या उनके खिलाफ़ कौन से अपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। एक जानकार वोटर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सकता है

सूचना आयुक्तराहुल सिंह ने आदेश जारी करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को कहा है कि सूचना आयोग के इस आदेश की प्रति जिले के समस्त कलेक्टरों को उपलब्ध कराकर पालन सुनिश्चित करवाए। इस आदेश में सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ४ के तहत स्वत: पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जारी करने के निर्देश दिए हैं ताकि इसके लिए आरटीआई भी ना लगाना पड़े।